सितंबर 2021
खंड - XXXVII | अंक - III

एक्ज़िमिअस:
निर्यात लाभ

इस अंक में

- भारत–अफ्रीका स्वास्थ्य सेवाएं– संभावना और अवसर
- खेल सामग्री उद्योग
- भारत में उदारीकरण के बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार विषय पर निबंध
- उत्तर प्रदेश से निर्यात संवर्धन
- भारत–जापान साझेदारी: व्यापार और अन्य संभावनाएं

तिमाही प्रकाशन

इंडिया एक्ज़िम बैंक

केन्द्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केन्द्र संकुल,
कफ परेड, मुंबई - 400 005.
फोनः 022 2217 2600
ईमेलः ccg@eximbankindia.in
www.eximbankindia.in
www.eximmitra.in

भारत–अफ्रीका स्वास्थ्य सेवाएं– संभावना और अवसर

अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति

कोविड-19 महामारी ने देशों के सामाजिक विकास की स्थिति पर पुनर्विचार करने की जरूरत महसूस कराई है। इससे एसडीजी (सतत विकास लक्ष्य)-3 और भी प्रासंगिक हो गया है। यह लक्ष्य है- `सभी उम्र के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और उनकी तंदुरुस्ती को प्रोत्साहन देना'। अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं ने खाद्य असुरक्षा, संक्रामक बीमारियों और गरीबी जैसी समस्याओं के बावजूद अपनी आबादी की बेहतर सेहत सुनिश्चित करने में काफी प्रगति की है। फिर भी अफ्रीका का स्वास्थ्य सेवा विकास कार्यक्रम अब भी असमान है। वैश्विक स्वास्थ्य विस्तार (यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज) के सेवा विस्तार सूचकांक (सर्विस कवरेज इंडेक्स) यानी यूएचसी एससीआई से इसका पता चलता है। अफ्रीका के सात देशों में 2017 के दौरान यूएचसी एससीआई वैश्विक औसत से काफी ज्यादा रहा। यूएचसी एससीआई का वैश्विक औसत जहां 66 था, वहीं अफ्रीकी औसत 46 रहा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार दुनियाभर में स्वास्थ्य सेवाओं पर 2018 में 8.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर खर्च हुए। इसमें से अफ्रीका में सिर्फ 1% ही खर्च हुआ। जबकि बीमारियों की वजह से पड़ने वाले वैश्विक आर्थिक बोझ के मामले में अफ्रीका की हिस्सेदारी 26% रही। ये

अफ्रीका में मृत्यु के मुख्य कारण– संक्रामक, मातृत्व, शिशु एवं पोषण संबंधी स्थितियां

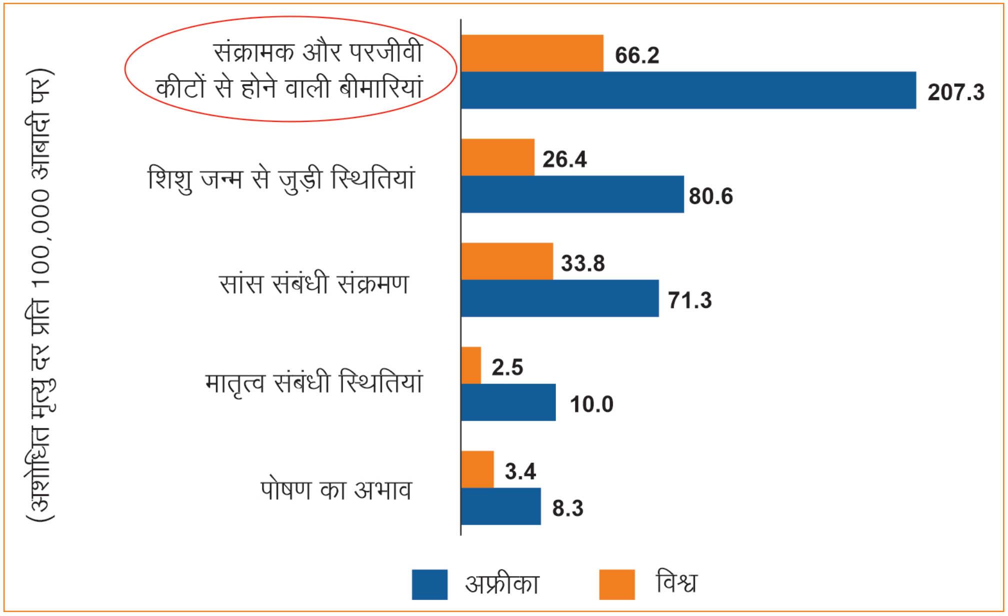

नोट : डब्ल्यूएचओ द्वारा परिभाषित अफ्रीकी क्षेत्र में 47 देश आते हैं
स्रोत : वैश्विक स्वास्थ्य आकलन 2019, डब्ल्यूएचओ ; और इंडिया एक्ज़िम बैंक विश्लेषण

आंकड़े इसकी जरूरत बताते हैं कि अफ्रीका के हर क्षेत्र में समान स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सकें, इसके लिए बहुआयामी प्रयास करने होंगे।

यूएनईसीए (अफ्रीका के लिए संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक आयोग) का अनुमान है कि अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च का अंतर सालाना 66 बिलियन यूएस डॉलर के करीब है। यानी वहां जरूरत से इतना कम खर्च हो रहा है। ऐसे में अगर 2030 तक अफ्रीका को एसडीजी-3 के लक्ष्य हासिल करने हैं तो लगभग 108 मिलियन यूएस डॉलर से 143 बिलियन यूएस डॉलर के अतिरिक्त संसाधन जुटाने की जरूरत होगी। देशों की विकास स्थिति के हिसाब से इसमें 19-20 का अंतर आ सकता है। वर्ष 2019 में अफ्रीका के सहारा उप-क्षेत्र में संक्रामक बीमारियों, मातृत्व संबंधी स्थितियों और पोषण आहार संबंधी परिस्थितियों के कारण वैश्विक औसत की तुलना में तीन गुना अधिक मौतें हुईं। जबकि दूसरी तरफ उत्तर अफ्रीका के देशों में, खासकर जिनमें प्रति व्यक्ति आय अधिक है, वहां गैर-संक्रामक बीमारियों की घटनाएं अधिक दिखीं।

हालांकि डब्ल्यूएचओ का अनुमान है कि संक्रामक बीमारियों की तुलना में 2030 तक गैर-संक्रामक बीमारियों से होने वाली मौतों का आंकड़ा अधिक हो जाएगा। अफ्रीका की आबादी 2050 तक बढ़कर दोगुनी 2.5 बिलियन होने का भी अनुमान है। इनमें से करीब 60% आबादी शहरों में रह रही होगी। ऐसे में आशंका है कि बढ़ती आबादी, शहरों के बढ़े घनत्व के साथ संक्रामक बीमारियों और स्वास्थ्य सुविधाओं के खराब आधारभूत ढांचे के घालमेल से सेहत संबंधी गंभीर दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। लिहाजा स्वास्थ्य सुविधाओं के आधारभूत ढांचे पर लगातार निवेश बढ़ाना ही एकमात्र रास्ता है, जो लंबी अवधि में अफ्रीका के लिए मददगार हो सकता है। जिससे कि एजेंडा-2063 के तहत उसकी आकांक्षाएं पूरी हो सकें और वह सतत विकास के लक्ष्य पा सके।

वरीयता प्राप्त 54 अफ्रीकी देशों में से 33 ऐसे हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर असर छोड़ने वाली किसी महामारी संबंधी चुनौती से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक (ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स)-2019 में ऐसा माना गया है। यही नहीं, लैंसेट के एक अध्ययन के अनुसार करीब 41 मिलियन अफ्रीकी लोगों को, जो वहां की आबादी का लगभग 3.1% हिस्सा हैं, कोविड-19 से संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ सकता है। वहां एचआईवी/एड्स, टीबी जैसी संक्रामक बीमारियों और गैर-संक्रामक बीमारियों की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर आशंका है कि भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी किसी भी बड़े आघात के दौरान मौतों का आंकड़ा बहुत ऊपर जा सकता है।

अफ्रीकी देशों की सरकारों पर बजट घाटे का दबाव बहुत ज्यादा है। इसलिए उनकी हदें भी संकुचित हैं। ऐसे में निजी क्षेत्र का निवेश उस दबाव को कम करने और अंतर को पाटने में काफी अहम होगा। निजी क्षेत्र का यह निवेश सरकारों के मौजूदा वित्तीय प्रयासों में पूरक की तरह काम आ सकता है। यह निवेश कई आयामों पर हो सकता है। जैसे- सरकारी साझेदारी, सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी), संयुक्त उपक्रम (जेवी) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के रूप में।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत-अफ्रीका सहयोग

भारत और अफ्रीका के बीच विकासात्मक सहयोग में स्वास्थ्य क्षेत्र एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है। यह मानव पूंजी और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए भी उतना ही अहम है। भारत लंबे समय से अफ्रीका के कई देशों के साथ जुड़कर वहां तमाम संक्रामक बीमारियों के उन्मूलन के लिए काम कर रहा है। इसके लिए भारत की ओर से इन देशों को जेनरिक दवाइयां और टीके आदि बेहद कम दामों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। भारत की ओर से कुछ विशेष अभियान भी शुरू किए गए हैं। जैसे- एचआईवी के इलाज के लिए `डॉलर अ डे' और टीबी के लिए `ओपन-सोर्स ड्रग डिस्कवरी' आदि। अभी जनवरी-मार्च 2021 में ही भारत की ओर से अफ्रीका को स्वदेशनिर्मित कोविड-19 टीकों की 24.4 मिलियन खुराकें भेजी गई हैं। इसी अवधि के दौरान विश्व को कुल 37.8% टीकों की आपूर्ति की गई। विभिन्न कार्यक्रमों के तहत यह आपूर्ति की गई, जैसे- व्यावसायिक निर्यात, कोवैक्स कार्यक्रम, मानवीय मदद आदि। वास्तव में, अफ्रीका के लिए भारत फार्मा उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। उसने 2010 में अफ्रीकी देशों को फार्मा उत्पादों का 1.3 बिलियन यूएस डॉलर का निर्यात किया था। यह 2019 में बढ़कर दोगुने से अधिक करीब 3.2 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। यह इस बात का प्रमाण है कि भारतीय उत्पादों की वहां कितनी मांग है और घरेलू उत्पादन कितना बढ़ाया जा सकता है।

अफ्रीका से हर साल औसतन 50,000 पर्यटक मेडिकल वीजा पर भारत आते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि भारत में उपलब्ध सस्ती स्वास्थ्य सुविधाओं की कितनी मांग है। अफ्रीका के स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत तीसरा सबसे बड़ा निवेशक भी रहा है। साल 2010 से 2019 के बीच अफ्रीका के स्वास्थ्य क्षेत्र में यूके और यूएसए के बाद भारतीय निवेश की हिस्सेदारी 19% रही है।

अफ्रीका के स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करने वाले प्रमुख देश

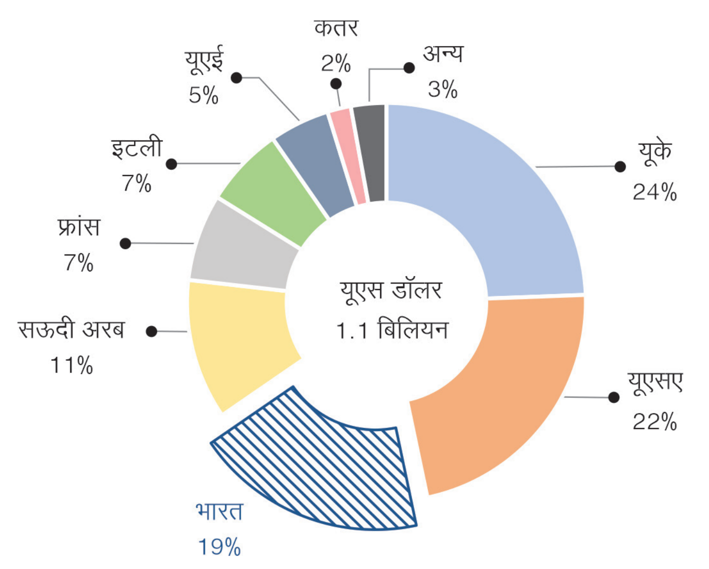

नोट : अफ्रीका के स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल निवेश जनवरी 2010 से दिसंबर 2019 के बीच 1.1 बिलियन यूएस डॉलर रहा। `एफडीआई मार्केट्स' दूसरे देशों से नई भौतिक परियोजनाओं के लिए आए निवेश पर नजर रखता है। साथ ही, नए रोजगार सृजन और पूंजीगत निवेश के विस्तार संबंधी परियोजनाओं पर भी निगाह रखता है। ये आंकड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अधिकृत आंकड़ों से अलग हो सकते हैं, क्योंकि कंपनियां स्थानीय स्तर पर पूंजी जुटा सकती हैं। निश्चित अवधि में चरणबद्ध निवेश कर सकती हैं। कर संबंधी झंझटों के मद्देनजर अन्य देशों के रास्ते भी निवेश ला सकती हैं।

स्रोत : एफडीआई मार्केट्स ऑनलाइन डाटाबेस और इंडिया एक्ज़िम बैंक विश्लेषण (3 दिसंबर, 2020 का आकलन)

इस साझेदारी को और मजबूत करने के लिए इंडिया एक्ज़िम बैंक के अध्ययन में 100 मिलियन यूएस डॉलर का कोष स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। इसके जरिए पूरे अफ्रीका में 100 बिस्तरों की क्षमता वाले छोटे अस्पतालों के निर्माण का प्रस्ताव है। इससे अफ्रीका में स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत ढांचे की कमी को कुछ भरा जा सकेगा। साथ ही मरीज भी बिना अतिरिक्त यात्रा खर्च के अस्पतालों की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। बड़े भारतीय अस्पताल समूहों को पीपीपी प्रणाली के तहत काम करने का अच्छा अनुभव है। वे अफ्रीकी स्वास्थ्य क्षेत्र के आधारभूत ढांचे से जुड़ी जरूरतों के लिए आदर्श साझेदार हो सकते हैं। अस्पतालों के निर्माण और प्रशासनिक इंतजामों के मामले में भारत की विशेषज्ञता है। भारत-अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से यह विशेषज्ञता दोतरफा लाभ का जरिया बन सकती है।

इंडिया एक्ज़िम बैंक के अध्ययन में यह भी सुझाव है कि अफ्रीकी देशों के सहयोग से वहां पर क्षेत्रीय दवा और टीका उत्पादन इकाइयां स्थापित की जाएं। अनुसंधान और विकास के लिए संयुक्त इकाइयां लगाई जाएं। साथ ही, पीपीपी मॉडल के आधार पर कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं विकसित की जाएं। इनसे पूरे अफ्रीका में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं का नेटवर्क भी बेहतर होगा।

इस अध्ययन में कुछ अन्य क्षेत्रों में भी द्विपक्षीय साझेदारी बेहतर करने का सुझाव दिया गया है। जैसे- अस्पताल प्रबंधन, सूचना-प्रौद्योगिकी का आधारभूत ढांचा निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य पर्यटन सुविधा, अफ्रीका में स्वास्थ्य केंद्रों (वेलनेस सेंटर) की स्थापना, अनुसंधान एवं विकास की संयुक्त पहल, क्षमता निर्माण व स्वास्थ्य प्रशिक्षण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवाचार आदि।

अफ्रीका में 2030 तक स्वास्थ्य और सेहत के क्षेत्र में करीब 259 बिलियन यूएस डॉलर के कारोबार के अवसर उपलब्ध होंगे। अफ्रीका महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (एफसीएफटीए) पूरे महाद्वीप में व्यावसायिक संभावनाओं को एकीकृत करेगा। यहां इस वक्त करीब 1.5 बिलियन आबादी है, जो 2050 तक 2.5 बिलियन हो सकती है। यानी यहां बाजार विस्तार की पूरी संभावनाएं मौजूद हैं, जिनको खंगाला जा सकता है। भारतीय अस्पताल समूह, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाली यहां की कंपनियां, दवा निर्माता और इसी क्षेत्र से जुड़ी अन्य उपक्रम अफ्रीकी साझेदारों के साथ अपनी साझेदारी की संभावना तलाश सकती हैं। उनके साथ जुड़कर बीमारियों से मुकाबले के लिए सुदृढ़ अफ्रीका के निर्माण में अपना योगदान दे सकती हैं। भारत-अफ्रीका साझेदारी को इससे नया आयाम मिल सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत-अफ्रीका साझेदारी मजबूत करने के लिहाज से कोविड-19 अवसरों के झरोखे की तरह सामने आया है। भारत की अफ्रीका के साथ चिकित्सा-कूटनीति `एजेंडा-2063' के हिसाब से भी एकदम सटीक बैठती है और अफ्रीका के लिए सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में भी उतनी ही उपयुक्त है। ऐसे में, भारत-अफ्रीका संबंधों के लिए स्वास्थ्य सेवा सुविधा का यह क्षेत्र अहम स्तंभ साबित होने वाला है।

16वें सीआईआई-एक्ज़िम डिजिटल कॉन्क्लेव के दौरान इंडिया एक्ज़िम बैंक के प्रकाशन का विमोचन

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (इंडिया एक्ज़िम बैंक) ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ 13 से 15 जुलाई 2021 के बीच 16वां डिजिटल कॉन्क्लेव आयोजित किया। इस सीआईआई-इंडिया एक्ज़िम बैंक डिजिटल कॉन्क्लेव की विषय वस्तु भारत-अफ्रीफा परियोजना साझेदारी रही। विदेश मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से कोविड-19 के दौर में लगातार दूसरे साल यह आयोजन आभासी माध्यम यानी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हुआ। इस तरह का पहला सम्मेलन 2005 में नई दिल्ली में हुआ था। इसके बाद साल-दर-साल भारत-अफ्रीका आर्थिक सहयोग को बेहतर करने और आपसी साझेदारी निर्माण के लिहाज से यह अग्रणी कार्यक्रम साबित हुआ। सम्मेलन अफ्रीकी बाजार में भारतीय परियोजनाओं के निर्यात और विस्तार के लिए सशक्त व सुविधानजक माध्यम बना। सम्मेलन के दौरान होने वाली उच्चस्तरीय वार्ताओं और विचार-विनिमय के स्पष्ट व उल्लेखनीय लाभ भारत और अफ्रीका के बीच बढ़े आर्थिक आदान-प्रदान के रूप में दिखे। सम्मेलन में भारत और अफ्रीका के कई नामी तथा प्रभावशाली शख्सियतों ने हिस्सा लिया। इन्होंने सक्रिय रूप से दोनों क्षेत्रों के बीच साझेदारी मजबूत करने में पुल की भूमिका निभाई। इस 16वें कॉन्क्लेव का उद्घाटन भारत के माननीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने किया। इसमें बोत्सवाना के माननीय उपराष्ट्रपति श्री स्लंबर सोगवाने, जिम्बॉम्वे के माननीय उपराष्ट्रपति और माननीय स्वास्थ्य एवं शिशु कल्याण मंत्री डॉक्टर श्री सी. जी. डी. एन. चिवेंगा, घाना के माननीय व्यापार एवं उद्योग मंत्री श्री एलन कैरीमैटेन विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन का उद्घाटन सत्र `भारत-अफ्रीका साझेदारी के लिए नए आयामों को निर्धारण' विषय पर केंद्रित था। इसमें दोनों क्षेत्रों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए चार क्षेत्र चिह्नित किए गए। पहला- सार्वजनिक स्वास्थ्य, दूसरा- डिजिटल डिलिवरी, तीसरा- कौशल विकास और क्षमता निर्माण तथा चौथा- हरित अर्थव्यवस्था। इस दौरान माननीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की उपस्थिति में `भारत-अफ्रीका स्वास्थ्य सेवाएं- संभावना और अवसर' शीर्षक से इंडिया एक्ज़िम बैंक का शोध अध्ययन भी जारी किया गया। इस मौके पर बोत्सवाना के माननीय उपराष्ट्रपति श्री स्लंबर सोगवाने, जिम्बॉम्वे के माननीय उपराष्ट्रपति और स्वास्थ्य एवं शिशु कल्याण मंत्री डॉ. सी. जी. डी. एन. चिवेंगा, घाना के व्यापार एवं उद्योग मंत्री श्री एलन कैरीमैटेन और इंडिया एक्ज़िम बैंक की उप-प्रबंध निदेशक सुश्री हर्षा बंगारी तथा कॉर्पोरेट क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ■

खेल सामग्री उद्योग

भारत का खेल सामग्री उद्योग चीन और जापान के बाद एशिया में तीसरा सबसे बड़ा है। भारतीय कंपनियां बीते कुछ सालों में 2018 के एशियाई खेलों जैसी अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए भी खेल सामग्री की आपूर्ति करने में सफल रही हैं। इंडिया एक्ज़िम बैंक के हालिया शोध अध्ययन `भारतीय खेल वस्तु उद्योगः निर्यात संभाव्यताओं के दोहन के लिए रणनीतियां' के मुताबिक, वर्तमान में भारत में 300 तरह की खेल सामग्रियों/उत्पादों का निर्माण किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में खेल सामग्री के उत्पादन में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। साल 2014-15 से 2018-19 के बीच 4.5% की सीएजीआर की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2018 में भारत में खेल सामग्री के उत्पादन का कुल मूल्य करीब 2,380.7 करोड़ रुपये था। हालांकि यह उत्पादन फिलहाल मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में ही केंद्रित है। एक- मेरठ, दूसरा- जालंधर। इन दोनों क्षेत्रों में देश की कुल खेल सामग्री का दो-तिहाई उत्पादन होता है।

यह उद्योग निर्यातोन्मुख है। देश में बनने वाली करीब 60% खेल सामग्री का निर्यात किया जाता है। वर्ष 2010-11 देश से खेल सामग्री का निर्यात 166.1 मिलियन यूएस डॉलर था। यह 2019-20 में 5.9% की बढ़ी हुई सीएजीआर के साथ 278.9 मिलियन यूएस डॉलर का हो गया। हालांकि यह अब भी कम ही है। वर्ष 2019-20 के भारत के कुल निर्यातों में खेल सामग्री का हिस्सा महज 0.09% ही रहा। वैश्विक बाजार के आकार के हिसाब से देखें तो भी भारत से निर्यात की जाने वाली खेल सामग्री की हिस्सेदारी कम ही है। भारत 2019 के दौरान विश्व में खेल सामग्री का 24वां सबसे बड़ा निर्यातक रहा। वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी महज 0.56% रही। इसके उलट भारत में खेल सामग्री का आयात तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2010-11 से 2019-20 के बीच 6.5% की सीएजीआर के साथ खेल सामग्री के आयात में वृद्धि दर्ज की गई। नतीजतन, भारत का व्यापार-अधिशेष 2019-20 में घटकर 2.8 मिलियन यूएस डॉलर रह गया। यह 2010-11 में 9.8 मिलियन यूएस डॉलर था।

अध्ययन में दिए गए विश्लेषण में खास उल्लेख किया गया कि भारत का खेल सामग्री उद्योग अंतरराष्ट्रीय मैदान में मौजूद अन्य प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले अभी बहुत पीछे है। इस क्षेत्र में कई एशियाई प्रतिस्पर्धी भी भारत से आगे हैं। बीते कुछ वर्षों में चीन, वियतनाम, थाईलैंड और पाकिस्तान जैसे देशों ने भी भारत को पछाड़ दिया है। इसका कारण यह है कि भारत की स्पर्धात्मकता खेल सामग्री के निर्यात के मामले में काफी कम है। साथ ही, भारत ने अपनी सामर्थ्य के कई परंपरागत क्षेत्रों में भी बाजार हिस्सेदारी गंवाई है।

भारत ने फुटबॉल के निर्यात के मामले में अपनी जमीन खोई है। इंडिया एक्ज़िम बैंक के विश्लेषण के अनुसार, 2010-11 में भारत से निर्यात होने वाली खेल सामग्रियों में फुटबॉल का दूसरा बड़ा हिस्सा था। यहां से खेल सामग्री के निर्यात में फुटबॉल की हिस्सेदारी 12% थी। लेकिन 2019-20 यह हिस्सेदारी घटकर 3.7% रह गई। इस तरह 2010-11 से 2019-20 के दौरान इसमें (-) 7.1% की सीएजीआर दर्ज की गई। ऐसे ही हवा भरी गेंदों की निर्यात हिस्सेदारी भी 2010 में जहां 2.4% थी, वहीं 2019 में 1.5% रह गई।

भारत से फुटबॉल के निर्यात में कमी का प्रमुख कारण यह रहा कि विश्व में मशीन से सिली हुई फुटबॉलों की मांग बीते कुछ वर्षों में बढ़ी है। जबकि भारत में अब भी अधिकांशतः हाथों से सिली हुई फुटबॉलों का ही उत्पादन होता है। इंडिया एक्ज़िम बैंक के विश्लेषण के अनुसार, वैश्विक बाजार में हाथ से सिली हुई फुटबॉल हर साल 45-50 मिलियन तक बिकती हैं। जबकि मशीन से बनी हुई फुटबॉलों की मांग और बिक्री इसकी लगभग दोगुनी तक होती है। पाकिस्तान और वियतनाम जैसे देशों ने तेजी से, सफलतापूर्वक इस परिवर्तन को अपनाया। इससे आज वे भारत को न सिर्फ कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहे हैं, बल्कि आगे हैं। पाकिस्तान आज बड़ी फुटबॉल प्रतिस्पर्धाओं के लिए शीर्ष आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर चुका है। इसमें फीफा और ओलंपिक जैसी प्रतिस्पर्धाएं भी शामिल हैं। `द एडिडास एल्बर्ट ऑफ द ओलंपिक्स 2012' और `एडीडास टेलस्टार 18 ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2018' दोनों के लिए ही पाकिस्तान से खेल सामग्री का आयात किया गया था।

भारत के लिए अपने खेल सामग्री बाजार को फिर हासिल करना एक बड़ी चुनौती है। उसके लिए उसे उत्पादन प्रक्रिया का बड़े पैमाने पर मशीनीकरण करना होगा। इस प्रक्रिया में मशीनों पर काफी निवेश की जरूरत होगी। खेल उद्योग में काम करने वाली अधिकांश इकाइयां चूंकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम (एमएसएमई) हैं। अतः जाहिर तौर पर उनके पास निवेश भी सीमित है। ऐसे में, सरकार इन इकाइयों को मशीनीकरण के लिए पूंजीगत सब्सिडी की सुविधा देने पर विचार कर सकती है। देशभर में खेल सामग्री के नए क्षेत्र स्थापित करने और आधारभूत ढांचे से जुड़ी सामान्य सुविधाएं विकसित करने की भी जरूरत है।

भारत में खेल सामग्री के उत्पादन के लिए मशीनीकरण ही नहीं, उसके मानकीकरण और प्रमाणन की प्रक्रिया भी एक चुनौती है। खेल सामग्री के निर्यातकों को विकसित बाजार में उत्पाद के निर्यात से पहले कई मानकों पर उसकी पुष्टि करानी होती है। इन प्रमाणपत्रों को हासिल करने में काफी लागत आती है। इस उद्योग में संचालित एमएसएमई के लिए यह लागत उठाना भी मुश्किल होता है। इसलिए वे इससे बचते हैं। इस दिशा में भी सरकार कुछ प्रोत्साहन देने वाले कदम उठा सकती है ताकि खेल सामग्री के निर्यात की स्थिति को सुधारा जा सके। मानकीकरण और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में आने वाले खर्च का 50% निर्यातकों को वापस लौटाने का विकल्प सरकार आजमा सकती है। हर निर्यातक इकाई के लिए इसकी सीमा भी तय की जा सकती है। इससे उन इकाइयों पर आने वाला वित्तीय बोझ कुछ कम होगा। खेल सामग्री के निर्यात के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी।

भारत से खेल सामग्री के निर्यात को बेहतर करने के उद्देश्य से किया गया खुदरा विश्लेषण यह संकेत भी करता है कि बाजार को ध्यान में रखकर नई रणनीति बनाने की जरूरत है। बाजार की विविधताओं का अध्ययन करते हुए उपयुक्त उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इंडिया एक्ज़िम बैंक के ही अध्ययन में टेनिस बॉल, टेबल टेनिस बॉल, गोल्फ बॉल आदि को ऐसे उत्पादों के तौर पर पहचाना गया है, जिनमें भारत के लिए बहुत संभावनाएं हैं। भारत से इन उत्पादों का निर्यात प्रतिस्पर्धी है और दुनिया में इनकी मांग भी तेजी से बढ़ रही है। लिहाजा, अल्पावधि और मध्यम अवधि में भारत इन उत्पादों पर ध्यान केंद्रित कर अवसरों का लाभ उठा सकता है। इस श्रेणी के उत्पाद भारत के लिए सुलभ हो सकते हैं। इनके अलावा छह और श्रेणियां हैं, जिन पर मध्यम और लंबी अवधि के लिहाज से ध्यान दिया जा सकता है। ये श्रेणियां हैं- `एथलेटिक्स एवं जिम्नेशियम उपकरण', `फेस्टिव आर्टिकल्स', `टेबल टेनिस वस्तुएं एवं उपकरण, टेनिस, बैडमिंटन व वैसे ही रैकेट', `फिशिंग उपकरण', `स्की एवं स्केटिंग उपकरण' और `वॉटर स्पोर्ट्स उपकरण'। ये श्रेणियां इस रूप में चिह्नित की गई हैं कि इनमें उम्मीद से कम सफलता मिलने के आसार हैं। ये ऐसे उत्पाद हैं, जिनकी 2010-2019 के बीच आयात मांग काफी रही है। लेकिन इन उत्पादों के मामले में भारत का निर्यात अभी प्रतिस्पर्धी नहीं है। इसलिए इस श्रेणी में घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। साथ ही इस श्रेणी की शीर्ष कंपनियों से अधिक निवेश और निर्यात ऑर्डर हासिल करने के प्रयास भी किए जा सकते हैं।

इसके अलावा, निर्यात बाजार की विविधता के लिहाज से देखें तो हर चिह्नित श्रेणी के उत्पादों के लिए उनके शीर्ष आयात बाजारों को लक्ष्य करना जरूरी होगा। तभी इस क्षेत्र के वैश्विक बाजार में भारत की निर्यात हिस्सेदारी बढ़ सकेगी। इसके अतिरिक्त, उन विभिन्न विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को भी लक्ष्य किया जा सकता है, जहां खेल सामग्री की मांग अधिक हो। उदाहरण के लिए ब्राजील, नाइजीरिया, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, चिली, कोलंबिया, अर्जेंटीना, पेरू और इक्वाडोर में खेल सामग्री की मांग काफी रहती है। भारत के निर्यातक इन बाजारों की विविधतापूर्ण मांगों को समझकर उनकी आपूर्ति के लिए इन्हें अपने निर्यात-स्थान बना सकते हैं।

भारत से निर्यातों के लिहाज से खेल सामग्री क्षेत्र में बीती कुछ अवधि में अच्छी वृद्धि की संभावना रही है। इंडिया एक्ज़िम बैंक के अनुमान के अनुसार खेल सामग्री उद्योग में 227.4 मिलियन यूएस डॉलर के निर्यात की संभावनाएं अंतर्निहित हैं। अगर इनका सही तरीके से दोहन किया गया तो इस क्षेत्र का निर्यात 500 मिलियन यूएस डॉलर तक भी पहुंच सकता है। भारत सरकार का पूरा ध्यान इस समय उत्पादन इकाइयों को आत्मनिर्भर बनाने पर है। इस क्षेत्र में संभावनाएं भी भरपूर हैं। अतः वक्त आ गया है कि खेल सामग्री के क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए सही सुधार किए जाएं। घरेलू क्षमताओं को बढ़ाया जाए। निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को सुधारा जाए। ताकि देश के लिए अधिक से अधिक संभावनाओं का दोहन किया जा सके।

माननीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री द्वारा इंडिया एक्ज़िम बैंक के शोध अध्ययन का अनावरण

माननीय केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने `भारतीय खेल वस्तु उद्योगः निर्यात संभाव्यताओं के दोहन के लिए रणनीतियां' शीर्षक से तैयार इंडिया एक्ज़िम बैंक के शोध अध्ययन का अनावरण किया। लखनऊ में `उभरते सितारे फंड' की शुरुआत के मौके पर इंडिया एक्ज़िम बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा 21 अगस्त, 2021 को आयोजित एक संयुक्त सेमिनार में इसका अनावरण किया गया। सेमिनार को वित्त मंत्रालय, इंडिया एक्ज़िम बैंक, सिडबी के वक्ताओं और एमएसएमई क्षेत्र के कई उद्यमियों ने संबोधित किया। भारत के कारोबारी समुदाय के करीब 500 प्रतिनिधियों ने इस सेमिनार में हिस्सा लिया। इनमें से कुछ मौके पर खुद उपस्थित थे, तो कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इससे जुड़े। ■

भारत में उदारीकरण के बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार विषय पर निबंध

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (इंडिया एक्ज़िम बैंक) ने 2016 में ब्रिक्स आर्थिक शोध वार्षिक पुरस्कार शुरू किया था। इस पुरस्कार का मकसद अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार, विकास और संबंधित वित्तपोषण के क्षेत्र में उन्नत सैद्धांतिक शोध को प्रोत्साहन देना है। विश्व में किसी भी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान से संबद्ध ब्रिक्स के पांचों सदस्य देशों के नागरिक इस पुरस्कार के पात्र हैं। वर्ष 2021 में इंडिया एक्ज़िम बैंक ब्रिक्स आर्थिक शोध वार्षिक पुरस्कार के लिए चयनित प्रविष्टि का शीर्षक है, 'भारत में उदारीकरण के बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर निबंध'। इस शोध प्रबंध के लेखक डॉ. राहुल सिंह हैं। वह गुजरात के अहमदाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध 'अमृत मोदी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट' (प्रबंध विद्यालय) में असिस्टेंट प्रोफेसर (सहायक व्याख्याता) हैं। डॉ. सिंह ने भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), बैंगलोर से 2020 में अपनी शोध उपाधि ली है।

भारत में आर्थिक उदारीकरण के बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में कुछ बड़े परिवर्तन देखने में आए हैं। व्यापारिक वार्ताओं का फोकस अब टैरिफ से नॉन-टैरिफ उपायों (एनटीएम) पर हो गया है, जो व्यापार के लिए प्रमुख बाधाओं के रूप में उभरे थे। इसी अवधि के दौरान 2009 में चीन दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा। भारत के विनिर्माण आयात में भी उसकी हिस्सेदारी बहुत तेजी से बढ़ी है। यह वर्ष 2000 में महज 5% थी। जबकि 2010 में बढ़कर 18% हो गई। इस पृष्ठभूमि में यह सवाल स्वाभाविक है कि इन परिवर्तनों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर हुआ। भारत अगर आयात कम करने वाले एनटीएम लागू करे तो भारतीय फर्मों पर इसके क्या परिणाम होंगे? चीन के साथ अचानक आयात प्रतिस्पर्धा बढ़ने से इसके प्रतिस्पर्धी प्रभाव कितने बड़े होने वाले हैं? चीन से ही आयात प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर श्रम-बाजार कैसे प्रभावित हुआ है?

देश में किए जा रहे व्यापार और फर्मों के प्रदर्शन के सामने तकनीकी बाधाएं

देश में किए जा रहे व्यापार के सामने तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) की घटनाएं 2000 के दशक की शुरुआत से लगातार बढ़ी हैं। टीबीटी के संभावित कारण स्वास्थ्य, उपभोक्ता संरक्षण और पर्यावरण जैसे सार्वजनिक नीतिगत उद्देश्यों से संबंधित हैं। लेकिन विभिन्न देश अपनी घरेलू फर्मों को अनुचित लाभ देने के लिए भी इन नियामक उपायों का उपयोग कर सकते हैं।

इस अध्ययन में इसी की पड़ताल की गई है कि भारत की उत्पादन फर्मों के प्रदर्शन पर प्रतिबंधात्मक टीबीटी उपायों का क्या असर हुआ है। भारतीय संदर्भ में यह विषय शोध के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। खास तौर पर इन तथ्यों के मद्देनजर कि भारत ने 1990 के दशक की शुरुआत से ही बड़े पैमाने पर आर्थिक उदारीकरण किया है। साथ ही, 2000 के दशक की शुरुआत से टीबीटी उपायों का इस्तेमाल बढ़ा है। उदारीकरण से भारतीय बाजार में आयात प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ी है। विदेशी मध्यवर्ती आदानों तक भारतीय विनिर्माण फर्मों की पहुंच भी बढ़ी है, जो पहले उनके लिए अनुपलब्ध थे। इस प्रकार उत्पादन तकनीक पर उदारीकरण से पहले की बाधाओं को दूर करने में मदद मिली है।

भारत द्वारा अपनी विनिर्माण फर्मों पर लागू किए गए प्रतिबंधात्मक टीबीटी के प्रभावों की पड़ताल एक विशिष्ट चैनल पर ध्यान केंद्रित कर की गई है। पड़ताल की गई कि आयातित मध्यवर्ती आदानों तक पहुंच के मामले में इन उपायों का क्या प्रभाव रहा। इन आदानों की अंतिम उपयोगकर्ता यानी घरेलू फर्मों की लाभकारिता और क्षमता पर क्या असर पड़ा। इस तरह की पड़ताल में अंतर्निहित तर्क यह है कि टीबीटी लागू करने वाले देश में आयात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसका कारण उत्पादन की बढ़ी हुई परिवर्तनीय लागत (जैसे- लेबलिंग आवश्यकताओं) या निश्चित लागत (मसलन- उत्पादन प्रक्रिया) से टीबीटी की संबद्धता है। इसीलिए टीबीटी इन नियामक उपायों को बनाए रखते हुए देश में फर्म स्तरीय प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि वे बेहतर तकनीक से लैस आयातित आदानों तक पहुंच कम कर करते हैं। इस कारण फर्मों तक उपलब्ध होने वाली प्राप्तियों की विविधता भी कम हो जाती है।

इस विश्लेषण के निष्कर्ष बताते हैं कि टीबीटी का घरेलू फर्मों के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आयातकों के लिए आयातित आदानों तक इन फर्मों की पहुंच कम होती है। आयातित आदानों पर टीबीटी लागू करने की प्रतिक्रिया में इनकी कार्यक्षमता और लाभकारिता भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। इसके अलावा, यह भी पाया गया है कि उन आयातकों के लिए प्रभाव अधिक स्पष्ट हैं जो निर्यात करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट गहन उद्योगों से जुड़े हैं। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि टीबीटी को बनाए रखना महंगा साबित हो सकता है। खास तौर पर तब जब वे आयातकों के लिए आयातित आदानों तक पहुंच में बाधा डालते हैं।

चीन का उभरना

चीन के विनिर्माण क्षेत्र ने 1990 और 2000 के दशकों में अपने उत्पादन में जबर्दस्त बढ़ोत्तरी की है। इसका नतीजा यह हुआ कि अधिकांश देशों में चीन से होने वाले आयात की हिस्सेदारी बढ़ी है। चीन के उत्पादन में यह वृद्धि आंतरिक सुधारों का नतीजा रही। इन सुधारों में ग्रामीण-शहरी प्रवास, विशेष आर्थिक क्षेत्र और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए तकनीक का स्थानांतरण प्रमुख रहे। चीन को 2001 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में शामिल किया गया। इसके बाद उसके निर्यात में और अधिक वृद्धि हुई। चीन से आयात बढ़ने का सबसे अधिक फायदा उपभोक्ताओं को हो सकता है। उन्हें घरेलू बाजार में कम दामों पर उत्पाद उपलब्ध हो सकते हैं। आयात प्रतिस्पर्धा के कारण घरेलू फर्में भी दो अलग-अलग स्तरों पर दाम घटाने के लिए मजबूर हो सकती हैं। एक- आयात प्रतिस्पर्धा फर्मों को दक्षता में सुधार करने और लागत में कमी लाने के लिए प्रेरित कर सकती है। साथ ही लागत में बचत करने का

असर कीमतें कम होने के रूप में सामने आ सकता है। दूसरा- बाजार की बड़ी फर्में भी अपने लाभांश और कीमतों का आंकड़ा नीचे गिरा सकती हैं। इस तरह, दोनों ही माध्यमों का रास्ता कीमतें कम करने की ओर जाता है। फिर भी कमी कितनी होगी यह इस पर अधिक निर्भर करता है कि लागत का कितना हिस्सा कीमत से वसूला जाता है। इतना ही नहीं, भारतीय फर्में चीन से आने वाले सामानों तक पहुंच बनाकर भी लाभ उठा सकती हैं। वे इसके जरिए अपनी लागत कम कर सकती हैं। यहां भी कीमत कितनी कम होती है, यह इसी पर निर्भर करता है कि लागत का कितना हिस्सा कीमत से वसूला जा रहा है।

खर्चों में जोड़े जाने वाले मूल्य (मार्कअप) से अलग सीमांत लागत पर आयात प्रतिस्पर्धा के प्रभाव को चिह्नित करना बहुत महत्त्वपूर्ण है। कारण है कि हर माध्यम उत्पादकों और उपभोक्ताओं के संपूर्ण कल्याण तथा उसके वितरण को अलग तरह से प्रभावित करता है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण मार्कअप में सीधी कमी से कीमतें घटती हैं और उत्पादक के अधिशेष के खर्च पर उपभोक्ताओं को अतिरिक्त विकल्प मिल जाते हैं। जब तक कीमतों में लागत के पासथ्रू की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती, आयात प्रतिस्पर्धा के कारण सीमांत लागत में कमी से मार्कअप बढ़ेगा। अगर पासथ्रू कम है तो लागत में बचत से फर्मों का मार्कअप बढ़ेगा और उपभोक्ताओं के लिए कम कीमतों के अतिरिक्त विकल्प में मामूली बढ़त होगी। बढ़ती प्रतिस्पर्धा का मार्कअप पर सीधा असर न हो, इसके लिए जरूरी है कि इस सीमांत लागत पर आयात स्पर्धात्मकता का प्रभाव नियंत्रित रहे। और इसके लिए हमें फर्म-उत्पाद स्तर पर कीमतों की निगरानी करनी होगी।

देखने में आया है कि चीन से आयात बढ़ने का निम्नलिखित पर असर पड़ा है: (1) भौतिक कार्यक्षमता में बढोत्तरी, (2) सीमांत लागत में कमी, (3) खर्चों में जोड़े जाने वाले मूल्य में बढ़त, (4) कीमतों में मामूली कमी, (5) अनुसंधान और विकास के खर्च में बढ़त और पूंजी गहनता, (6) उत्पाद के स्कोप पर गैर-मामूली प्रभाव। कीमतों पर लागत बचत का अपूर्ण पासथ्रू टुकड़ों में और समय के साथ पाया गया है। आयात प्रतिस्पर्धा और आयातित वस्तुओं तक पहुंच, दोनों के कारण लागत बचत से मार्कअप में वृद्धि हुई। शोध अध्ययन में पाया गया है कि विशिष्ट फर्मों के आधार पर फर्मों की प्रतिक्रिया में उल्लेखनीय विविधता रही है। पहला तो यह पाया गया कि जिन फर्मों की सीमांत लागत पहले ही कम है, उन्होंने अलग तरह से इसे और नीचे लाया, अपना मार्कअप और उत्पाद का दायरा भी बढ़ाया। वहीं, जिन फर्मों की सीमांत लागत पहले ही अधिक रही, वे ऐसा नहीं कर सकीं। दूसरी बात, बड़े कारोबारी समूह और विदेशी मालिकों वाली फर्मों का कीमतों में लागत पासथ्रू पहले ही कम रहा। इससे बड़े पैमाने पर उनका मार्कअप बढ़ा। जबकि अन्य निजी कंपनियां अपनी लागत बचत का अधिकांश हिस्सा कीमतों पर डाल देती हैं। इसलिए उनके मार्कअप में भी उल्लेखनीय बढ़त नहीं देखी गई।

अध्ययन में बताया गया है कि चीन से आयात बढ़ने का फायदा प्राथमिक रूप से उन उत्पादकों को हुआ, जिन्होंने लागत में बड़े पैमाने पर कमी देखी और मार्कअप बढ़ाया। वह भी उत्पादों की कीमतें बहुत मामूली बढ़ाकर। ये नतीजे बताते हैं कि चीनी आयात की प्रतिस्पर्धा ने फर्मों को अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने और लागत कम करने पर मजबूर किया है। यही नहीं, चीन से आयातित उत्पादों तक पहुंच के कारण औपचारिक फर्मों को बड़े पैमाने पर लाभ भी हुआ। कारण कि इससे उनकी लागत घटी और मार्कअप में वृद्धि हुई।

चीन से आयात प्रतिस्पर्धा और कॉन्ट्रैक्ट पर श्रमबल

भारत में 1990 के दशक के बाद से विनिर्माण रोजगार के स्वरूप में ढांचागत बदलाव आया है। फर्मों ने अपने कार्यबल में कॉन्ट्रैक्ट पर श्रमबल की तादाद काफी बढ़ाई है।

अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि चीन से आयात प्रतिस्पर्धा ने कॉन्ट्रैक्ट आधारित रोजगार को बढ़ावा दिया है। फर्म के भीतर भी (लागत बचाने के लिहाज से) और दो फर्मों के बीच भी (संरचना के हिसाब से)। जहां तक फर्मों के भीतर का मामला है, तो चीन से आयात प्रतिस्पर्धा के चलते सभी को अल्पावधि की लागत बचत का मार्ग अपनाया। इसके लिए उन्होंने अपने कार्यबल में कॉन्ट्रैक्ट पर श्रमबल की तादाद बढ़ाई, क्योंकि यह सस्ता होता है। वहीं, जहां श्रम संगठन मजबूत हैं, वहां बड़े उत्पादन वाली फर्मों ने अपने कार्यबल में अलग तरह से कॉन्ट्रैक्ट श्रमबल की हिस्सेदारी बढ़ाई है। ऐसा करके उन्होंने अपने नियमित कामगारों की मोलभाव करने की क्षमता को सीमित करने का प्रयास किया। इसमें भी हालांकि योगदान चीन से आयात प्रतिस्पर्धा का ही रहा। ऐसा अनुमान है कि इस तरह का प्रभाव उन राज्यों में अधिक होगा, जहां श्रम संगठनों को मजबूती देने वाले नियम-कानून हैं। इसके अलावा, यह भी अनुमान लगाया गया कि चीनी आयात प्रतिस्पर्धा उत्पादन और संसाधनों को उच्च उत्पादकता और उच्च कॉन्ट्रैक्ट आधारित रोजगार फर्मों की ओर स्थानांतरित करती है। इस प्रकार उद्योग में कुल कॉन्ट्रैक्ट आधारित रोजगार की हिस्सेदारी बढ़ती है। पुनर्आवंटन प्रभाव भी आंतरिक प्रभाव में आता है। कारण कि यह शुरू में उत्पादक फर्मों को रोजगार के अपने कॉन्ट्रैक्ट आधारित हिस्से को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि वे अक्सर फर्म स्तर पर समय के साथ बड़े और मजबूत हो चुके श्रम संगठनों का सामना करते हैं।

इन नतीजों के मुताबिक चीन से आयात प्रतिस्पर्धा की प्रतिक्रिया स्वरूप औपचारिक फर्मों में कॉन्ट्रैक्ट आधारित रोजगार में काफी वृद्धि हुई है। आंतरिक फर्म प्रभाव उन बड़ी और उत्पादक फर्मों द्वारा संचालित होते हैं, जो फर्म स्तर पर मजबूत श्रम संगठनों का सामना करते हैं। आगे यह प्रभाव उन राज्यों में और बड़े रूप में देखा जाता है, जहां मजबूत श्रम संगठन सक्रिय हैं। इस विश्लेषण में संरचना प्रभाव का प्रमाण भी मिलता है, जिसमें आयात प्रतिस्पर्धा की प्रतिक्रिया में रोजगार में कॉन्ट्रैक्ट आधारित श्रम की हिस्सेदारी बढ़ जाती है। एक अनुमान के अनुसार, वर्ष 1998 से 2007 के बीच देश में कॉन्ट्रैक्ट आधारित श्रमिकों की कुल संख्या में से 9% चीन से आयात की प्रतिस्पर्धा में ही बढ़ी।

कुल मिलाकर ये नतीजे संकेत करते हैं कि बढ़ी हुई आयात प्रतिस्पर्धा अहम निर्धारक रही है। इसने फर्मों को अधिक से अधिक संख्या में कॉन्ट्रैक्ट श्रमबल को काम पर लगाने का निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके अलावा, अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है कि चीनी आयात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के प्रत्युत्तर में कॉन्ट्रैक्ट श्रमबल की संस्थापना, फर्मों में श्रमिकों के पुनः आवंटन को भी सक्षम बनाती है। इससे समग्र उत्पादकता में लाभ प्राप्त होता है। ■

उत्तर प्रदेश से निर्यातों का संवर्धन

उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यह करीब 246,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। देश के कुल भूभाग में 7.3% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है। यह राज्य जीएसडीपी (प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद[1]) के मामले में भी देश में चौथे नंबर पर आता है। वर्ष 2019-20 में देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 7.9% रही।

हालांकि वाणिज्यिक वस्तुओं के निर्यात के मामले में प्रदेश की हिस्सेदारी 2020-21 में महज 5.6% ही रही। व्यापक आर्थिक (मैक्रो इकोनॉमिक) मापदंडों में राज्य की हिस्सेदारी के हिसाब से देखें तो निर्यात में उसका हिस्सा बहुत कम है। यह स्थिति उत्तर प्रदेश के लिए इस जरूरत पर बल देती है कि वह राज्य से निर्यातों को बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाए।

उत्तर प्रदेश आम तौर पर अपने पारंपरिक उद्योगों के लिए जाना जाता है। जैसे- हस्तशिल्प उत्पाद, चमड़े का बना सामान, कालीन, कपड़े, शक्कर, सूत, जूट, वनस्पति तेल, कांच के सामान, चूड़ी आदि। पूर्वी उत्तर प्रदेश में शक्कर के उत्पादन में काफी बढ़त देखी गई है। इसका कारण कच्चे माल की सहज उपलब्धता और नई इकाइयों की स्थापना है। इसका परिणाम यह हुआ कि आज उत्तर प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा शक्कर उत्पादक बनकर उभरा है। राज्य में खनिज आधारित उद्योग भी उन्नत अवस्था में हैं। साथ ही, बड़ी संख्या में पशुओं की उपलब्धता से चमड़ा उद्योग भी फल-फूल रहा है।

वर्ष 2020-21 में कुल मूल्य के निर्यात के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश में पांचवें स्थान पर रहा। यहां से 2020-21 में 16.4 बिलियन यूएस डॉलर के वाणिज्यिक उत्पादों का निर्यात किया गया। जबकि 2015-16 में यह निर्यात 12.4 बिलियन यूएस डॉलर का ही था। उत्तर प्रदेश से वाणिज्यिक वस्तुओं के निर्यात में वित्तीय वर्ष 2016 से वित्तीय वर्ष 2021 के बीच 6% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। जबकि इस दौरान देश से होने वाले निर्यात में यह वृद्धि दर 2.4% ही थी। इस अवधि के दौरान निर्यात में इस वृद्धि की बदौलत

उत्तर प्रदेश से वाणिज्यिक निर्यात का प्रवाह

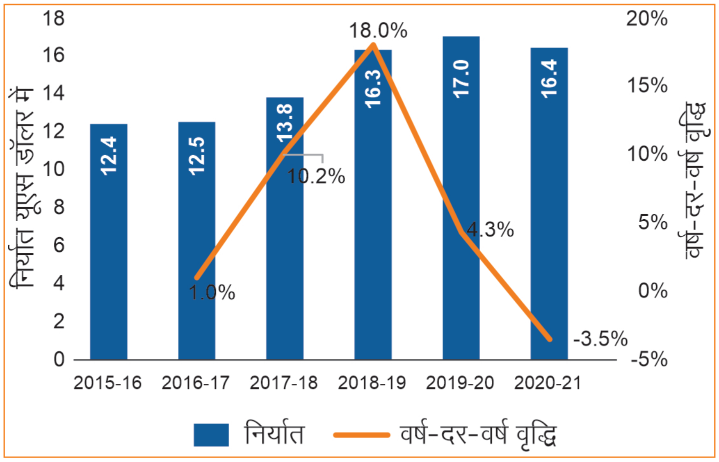

स्रोत : डीजीसीआईएस इंडिया एक्ज़िम बैंक शोध

उत्तर प्रदेश ने देश के कुल निर्यातों में अपनी हिस्सेदारी 2015-16 की 4.7% के मुकाबले 2020-21 में 5.6% कर ली है। प्रदेश से निर्यात-वृद्धि की एक अहम वजह यह रही कि यहां उत्पादन और निर्यात के लिए अनुकूल नीतिगत परिवेश मिला। प्रदेश से निर्यात के लिए अमेरिका सबसे बड़ी जगह साबित हुआ है। प्रदेश से 2020-21 में किए गए कुल निर्यात में 17.8% अमेरिका के लिए किया गया। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (7.4% हिस्सेदारी), जर्मनी (6.6%), नेपाल (6.0%), यूके (5.6%) और हांगकांग (4.2%) का स्थान रहा। वर्ष 2020-21 में प्रदेश से होने वाले कुल वाणिज्यिक निर्यात का 18.6% हिस्सा महाराष्ट्र के न्हावा शेवा बंदरगाह से गया। इसके बाद प्रदेश के निर्यात के लिए सीजीएमएल दादरी (16.9% हिस्सेदारी), दिल्ली हवाई अड्डा (9.2%), सीएफएस अल्बाट्रॉस/आईसीडी दादरी (8.0%) और आईसीडी नोएडा-दादरी (5.0%) का क्रम रहा। यानी प्रदेश का अधिकांश वाणिज्यिक निर्यात या तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बंदरगाहों से हुआ या अन्य राज्यों के रास्ते हुआ। इसके मद्देनजर पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यापार अनुकूल आधारभूत ढांचा और वृहद् क्षमता निर्माण की जरूरत महसूस होती है।

प्रदेश से जिन महत्त्वपूर्ण उत्पादों का निर्यात हुआ, उनमें दूरसंचार उपकरण (वित्तीय वर्ष 2021 के कुल वाणिज्यिक निर्यात में 15% हिस्सेदारी) सबसे ऊपर रहे। इसके बाद भैंस का मांस (11.4%), लौह-इस्पात के उत्पाद (3.8%), एल्युमीनियम और एल्युमीनियम के उत्पाद (3.7%), सूती रेडीमेड कपड़े और अन्य सामान (3.7%) और हाथ से बने धागे के रेडीमेड कपड़े (3.7%) आदि चीजें प्रमुख रहीं।

उत्तर प्रदेश में अब भी करीब 12.2 बिलियन यूएस डॉलर के अतिरिक्त वाणिज्यिक निर्यात की संभावनाएं निहित हैं।[2] अगर इन संभावनाओं का दोहन कर लिया जाए तो उत्तर प्रदेश का वाणिज्यिक निर्यात 30 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच सकता है। इन संभावनाओं को धरातल पर लाने के लिए राज्य को नए सिरे से निर्यात-रणनीति बनानी होगी। इस रणनीति में उन उत्पादों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना होगा, जिनमें अधिकतम वृद्धि की संभावनाएं हों। साथ ही, मांग और आपूर्ति के पहलुओं को भी ध्यान में रखना होगा। उत्तर प्रदेश के निर्यात से जुड़ा विश्लेषण से संकेत मिलता है कि वहां करीब 103 उत्पाद एचएस-6 अंकीय स्तर पर हैं। ये उत्पाद निर्यात के लिहाज से `चैंपियन" हो सकते हैं। ये ऐसे उत्पाद हैं, जिनमें प्रदेश का निर्यात प्रतिस्पर्धी है। साथ ही वैश्विक स्तर पर इनकी आयात मांग भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे उत्पादों में इलेक्ट्रॉनिक (विशेष रूप से मोबाइल फोन), मांसाहारी उत्पाद, बहुमूल्य धातुओं की बनी चीजें, लौह और इस्पात की वस्तुएं, एल्युमीनियम, तांबा, चावल जैसे अनाज, मेंथोल, कपड़े, जूते-चप्पल, चमड़े के उत्पाद, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, वाहनों के कलपुर्जे आदि प्रमुख हैं। छोटी से मध्यम अवधि में उत्तर प्रदेश इस श्रेणी के उत्पादों पर ध्यान केंद्रित कर निर्यात अवसरों का लाभ उठा सकता है, क्योंकि इस श्रेणी के उत्पाद उसके लिए सुलभ हैं।

राज्य को अल्पावधि और मध्यम अवधि में उस श्रेणी में क्षमता विकास पर फोकस करने की जरूरत है, जिस श्रेणी में प्रदर्शन, वैश्विक मांग बढ़ने के बावजूद, अभी अपेक्षा अनुरूप नहीं रहा है। हालांकि, उत्तर प्रदेश के निर्यातक इस

[1] स्थिर कीमतों पर, आधार वर्ष 2011-12 एमओएसपीआई

[2] आईटीसी एक्सपोर्ट पोटेंशियल मैप

क्षेत्र में उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। इनमें पेट्रोलियम उत्पाद, फार्मासूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कलपुर्जे, मशीनों के कलपुर्जे, प्लास्टिक की वस्तुएं आदि शामिल हैं। इन उत्पादों के लिहाज से प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की बेहद जरूरत है।

राज्य को उच्च मूल्य संवर्धित वस्तुओं की ओर अपने निर्यात को मोड़ने की भी जरूरत है। निर्यातों को विस्तार देने का एक प्रभावी तरीका यह हो सकता है कि मूल्य संवर्धन के आधार पर उत्पादों की विविधता की ओर देखा जाए। निर्यात विविधता के दो तरीके प्रचलित हैं। एक- क्षैतिज यानी होरिजोंटल और दूसरा- लंबवत् अर्थात वर्टिकल विविधीकरण। क्षैतिज विविधीकरण को उसी क्षेत्र के भीतर मौजूदा निर्यातों में ही नए उत्पाद जोड़कर आकार दिया जाता है। जबकि लंबवत् विविधीकरण की प्रक्रिया के तहत प्राथमिक से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की ओर से परिवर्तन अपरिहार्य है। मतलब लंबवत् विविधकरण के तहत मौजूदा उत्पादों के साथ ही मूल्य संवर्धित सेवाएं जोड़नी होंगी। उन्हें संसाधित करने और उनकी मार्केटिंग जैसी सेवाओं पर ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिए, कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में लंबवत् विविधीकरण पर बड़े रूप में ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। जैसे- ओलेओरेसिन (प्राकृतिक और कृत्रिम मिश्रण) के रूप में संसाधित मसाले राज्य के निर्यात के लिए उभरता अवसर हो सकते हैं।

विनिर्माण के क्षेत्र में टेक्सटाइल (कपड़ा) क्षेत्र में निर्यात की काफी संभावनाएं हैं। हालांकि राज्य सरकार ने टेक्सटाइल और उससे जुड़े उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाए हैं। बड़े पैमाने पर निवेश भी आकर्षित किया है। फिर भी विशेष रूप से घरेलू टेक्सटाइल और तकनीकी टेक्सटाइल के क्षेत्र में टेक्सटाइल मूल्य संवर्धन श्रृंखला के विविधीकरण की जरूरत महसूस की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरी क्षेत्र भी उभरता हुआ दिख रहा है। राज्य को इस उच्च तकनीक वाले क्षेत्र में उत्पादन और निर्यात क्षमताएं बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसलिए क्योंकि कृषि उत्पादों की तुलना में ये कम अस्थिर होते हैं। ये क्षेत्र राज्य में उच्च-कौशल वाला रोजगार भी पैदा कर सकते हैं। प्रदेश लीथियम ऑयन, स्टैटिक कन्वर्टर, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स और चिकित्सा उपकरण व सामान आदि के उत्पादन व निर्यात को भी बढ़ावा दे सकता है। ये ऐसे उत्पाद हैं, जिनकी वैश्विक आयात में हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है।

व्यापार-व्यसाय के आधारभूत ढांचे में अभी जो कमियां हैं, उन्हें दूर करके प्रदेश अपनी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सकता है। नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक के अनुसार परिवहन-संपर्क के सभी मानकों पर उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन कमतर है। अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की तुलना में इसे सबसे कम अंक मिले हैं। स्पष्ट है कि इस मुख्य मानक पर राज्य को सुधार करने की बेहद जरूरत है। इसके लिए राज्य को अधिक से अधिक आईसीडी स्थापित करनी होंगी। एयर-कार्गो सुविधाएं विकसित करनी होंगी। बंदरगाहों तक संपर्क भी दुरुस्त करना होगा।

माननीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री द्वारा इंडिया एक्ज़िम बैंक के शोध अध्ययन का अनावरण

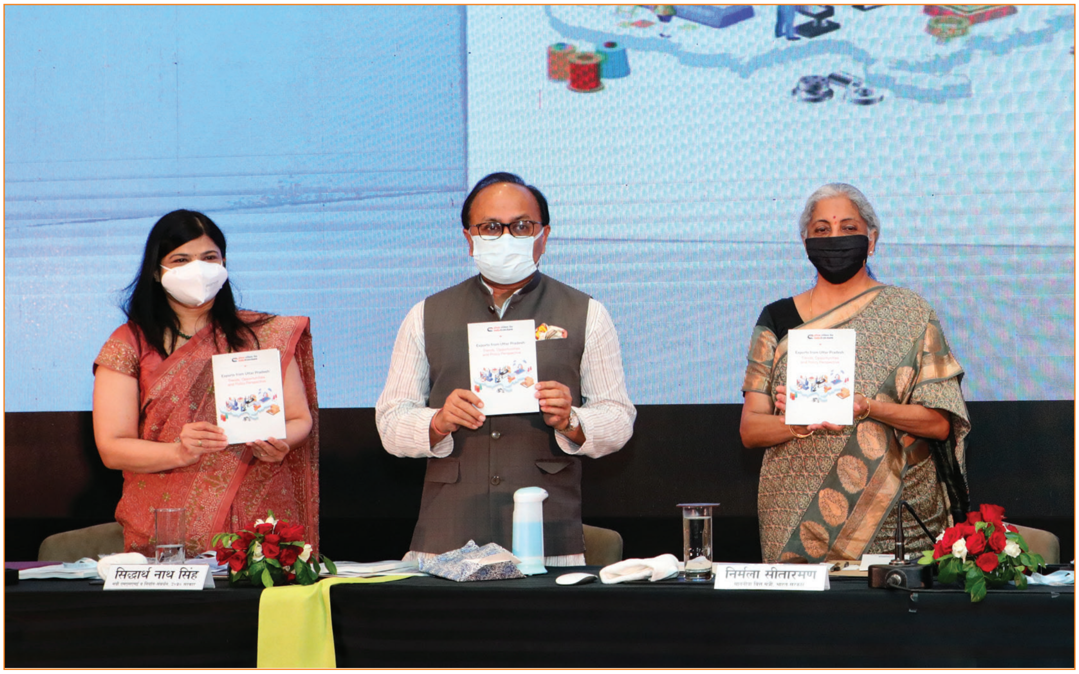

माननीय केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रीश्रीमती निर्मला सीतारमण ने `उत्तर प्रदेश से निर्यातः रुझान, अवसर और नीतिगत परिप्रेक्ष्य' शीर्षक से तैयार इंडिया एक्ज़िम बैंक के शोध अध्ययन का अनावरण किया। लखनऊ में `उभरते सितारे फंड' की शुरुआत के मौके पर इंडिया एक्ज़िम बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा 21 अगस्त, 2021 को आयोजित एक संयुक्त सेमिनार में इसका अनावरण किया गया। सेमिनार को वित्त मंत्रालय, यूपी सरकार इंडिया एक्ज़िम बैंक, सिडबी के वक्ताओं और एमएसएमई क्षेत्र के कई उद्यमियों ने संबोधित किया। भारत के कारोबारी समुदाय के करीब 500 प्रतिनिधियों ने इस सेमिनार में हिस्सा लिया। इनमें से कुछ मौके पर खुद उपस्थित थे, तो कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इससे जुड़े।

भारत-जापान साझेदारी : व्यापार और अन्य संभावनाएं

एशिया की दो बड़ी शक्तियां भारत और जापान रणनीतिक साझेदार हैं। उनके हित भी समान हैं। दोनों ही विश्व में और विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि देखना चाहते हैं। राजनीतिक उदारीकरण, बाजार अर्थव्यवस्था और कानून व लोकतंत्र का शासन जैसे मूल्य भी भारत-जापान के लिए समान हैं।

वर्षों से भारत के विकास में जापान एक अहम साझेदार रहा है। जापान 1958 से ही भारत को द्विपक्षीय कर्ज और वित्तीय सहायता देता आ रहा है। भारत के लिए आज भी जापान ही सबसे बड़ा द्विपक्षीय वित्तीय सहयोगी है। भारत में आर्थिक विकास तेज करने के लिए जापान की अधिकृत विकास सहायता (ओडीए) एजेंसी लगातार मदद दे रही है। विशेष रूप से ऊर्जा, परिवहन, पर्यावरण और मानवीय आवश्यकताओं से जुड़ी मूलभूत परियोजनाओं के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में। दिल्ली मेट्रो भारत-जापान साझेदारी और ओडीए की वित्तीय मदद के सदुपयोग की उज्ज्वल मिसाल है। मुंबई-अहमदाबाद हाईस्पीड रेल, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर (डीएफसी), 12 औद्योगिक नगरों के साथ बन रहा दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा, चेन्नई-बेंगलूरु औद्योगिक गलियारा (सीबीआईसी), आदि इस सहयोग के कुछ ताजा उदाहरण हैं। ये सभी बड़ी परियोजनाएं ऐसी हैं, जो आने वाले दशक में भारत की शक्ल-ओ-सूरत बदल देंगी। जापानी ओडीए ने वित्तीय वर्ष 2018-19 भारत के लिए 537.4 बिलियन येन की सहायता स्वीकृत की, जो ऐतिहासिक ऊंचाई वाला आंकड़ा है।

भारत-जापान व्यापार

भारत और जापान के बीच 16 फरवरी, 2011 को समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर दस्तखत किए गए। इसका मकसद जापान से भारत के लिए किए जा रहे 90% निर्यात पर से शुल्क हटाना था। जैसे- आॅटो पुर्जे, इलेक्ट्रिक उपकरण आदि। इसी तरह जापान के लिए हो रहे भारत से 97% आयात को भी शुल्क मुक्त करने का प्रावधान है। इन उत्पादों में कृषि और मत्स्य उत्पाद प्रमुख हैं। इन प्रावधानों को दोनों तरफ से अमल में लाने की समय सीमा 2021 तक रखी गई है। भारत ने अब तक जितने भी देशों से इस तरह के व्यापारिक समझौते किए हैं, उन सभी में सीईपीए सबसे विस्तृत और समग्र स्वरूप वाला है। इस समझौते के बाद भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय व्यापार भी बढ़ा है। यह 2010 में 13.1 बिलियन यूएस डॉलर का था। जबकि 2019 में बढ़कर 17.6 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। इसके बावजूद जापान के लिए भारत का निर्यात 2019 में भी 2010 के स्तर पर ही रहा। जापान के लिए भारत के निर्यात में 2011 से 2013 के बीच अच्छी बढ़त देखी गई। यह 2013 में तो 7.3 बिलियन यूएस डॉलर की ऐतिहासिक ऊंचाई तक पहुंच गया था। लेकिन इसके बाद से लगातार कम होता जा रहा है। यह सीईपीए से भी पहले के स्तर पर पहुंच गया है। भारत से जापान के लिए निर्यात किए जाने वाले उत्पादों में पेट्रोलियम उत्पाद प्रमुख हैं। इसके बाद जैविक रसायन, मछली और जलीय जीव, प्राकृतिक और परिष्कृत मोती, कीमती और थोड़े कम कीमती नग, मशीनरी तथा यांत्रिक उपकरण आदि शामिल हैं। वहीं भारत के लिए जापान से आयात में 2010 से 2019 के बीच 53% की वृद्धि हुई है। यह 2010 में 8.3 बिलियन यूएस डॉलर का था। जबकि 2019 में 12.7 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। जापान से भारत आने वाले प्रमुख सामानों में मशीनरी और यांत्रिक उपकरण शामिल हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक, लौह एवं इस्पात, प्लास्टिक, तांबा और इनके उत्पादों का नंबर आता है।

परिणामस्वरूप, भारत लगातार जापान के साथ व्यापारिक घाटे में चल रहा है। यह एक दशक में दोगुने से भी अधिक बढ़ा है। जापान के साथ भारत का व्यापार घाटा 2009 में 3.5 बिलियन यूएस डॉलर था। जबकि 2019 में यह 7.9 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। जापान से लगातार बढ़ते आयात के मद्देनजर जिन क्षेत्रों में भारत को सबसे अधिक व्यापारिक घाटा हो रहा है, वह है मशीनरी। सिर्फ इसी क्षेत्र में भारत को 3 बिलियन यूएस डॉलर का घाटा है। जबकि इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के क्षेत्र में 1.2 बिलियन यूएस डॉलर का घाटा है। इसके बाद लौह-इस्पात, प्लास्टिक, तांबा और उसके बने उत्पादों पर व्यापारिक घाटा हो रहा है।

भारत की निर्यात संभावनाएं

यह गौर करने लायक है कि जापान द्वारा किए जा रहे आयात में भारत की हिस्सेदारी 3% के करीब है। इसे अच्छा माना जा सकता है। हालांकि जापान के वैश्विक आयात में से अब तक तीन श्रेणियों में ही भारत अपनी जगह बना पाया है। ये हैं- जैविक रसायन, प्राकृतिक या परिष्कृत मोती, कीमती व थोड़े कम कीमती नग और मछली तथा जलीय जीव। जबकि जापान के आयात की अन्य श्रेणियों में भारत की हिस्सेदारी अब भी नगण्य है। भारत के पास अभी जापान के लिए 3.2 बिलियन यूएस डॉलर की निर्यात संभावनाएं मौजूद हैं, जिनका ठीक से दोहन नहीं किया गया है। इंडिया एक्ज़िम बैंक के शोध के अनुसार जापान के लिए भारत कई श्रेणियों में अपना निर्यात बढ़ा सकता है। जैसे- खनिज ईंधन और तेल, इलेक्ट्रिकल मशीनरी व उपकरण, मशीनरी एवं यांत्रिक उपकरण, ऑप्टिकल, फोटोग्राफिक उपकरण, फार्मासूटिकल उत्पाद, कपड़े आदि।

जापान को भारत के निर्यातों पर कई मुद्दों का असर पड़ा है। इनमें टैरिफ और नॉन-टैरिफ संबंधी दोनों ही तरह की बाधाएं हैं। नॉन-टैरिफ संबंधी दिक्कतों में व्यापार पर तकनीकी बाधाएं (टीबीटी) हैं। साथ ही सैनिटरी और फायटोसैनिटरी (एसपीएस) उपाय भी हैं। इंडिया एक्ज़िम बैंक ने `स्टडी ऑन नॉन टैरिफ मेजर्स' शीर्षक से एक अध्ययन किया है। इसके मुताबिक जापान में भारत के निर्यात हित वाले उत्पादों पर औसतन शुल्क 7% है। यह समग्र रूप से देश के टैरिफ के साधारण औसत (4%) से अधिक है।

जापान को निर्यात किए जाने वाले भारतीय हित के उत्पादों पर भी सीमा शुल्क बहुत ज्यादा है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, चावल, कपड़ा, चमड़ा, जूते और कुछ खाद्य प्रमुख हैं। लिहाजा, सीईपीए की समीक्षा के लिए आगामी बातचीत के दौरान भारत यह मुद्दा उठा सकता है। इन श्रेणियों के उत्पादों पर शुल्क कटौती की मांग कर सकता है। भारत को अगर 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की अर्थव्यवस्था का अपना लक्ष्य हासिल करना है तो उसे अपना निर्यात 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक बढ़ाना होगा। इस दिशा में भारत के लिए जरूरी है कि वह अपने व्यापार समझौतों का इस तरह इस्तेमाल करे कि उसे अधिक से अधिक लाभ हो सके। ■

इंडिया एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्थाएं

इंडिया एक्ज़िम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों,संप्रभु सरकारों और अन्य विदेशी संस्थाओं को ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है। ये ऋण-व्यवस्थाएं उन देशों के क्रेताओं को भारत से विकासपरक तथा बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं, उपकरण, माल एवं सेवाओं का आयात करने में समर्थ बनाती हैं। इंडिया एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के आदेश पर भी ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है। इनके अंतर्गत इंडिया एक्ज़िम बैंक माल के शिपमेंट पर भारतीय निर्यातकों को कॉन्ट्रैक्ट मूल्य के100 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करता है,बशर्ते कि कुल कॉन्ट्रैक्ट मूल्य के कम से कम 75 प्रतिशत के माल एवं सेवाओं का आयात भारत से किया गया हो। ऋण-व्यवस्थाओं के जरिए उभरते बाजारों में भारत की परियोजना निष्पादन क्षमता के प्रदर्शन में भी मदद मिली है। हाल के वर्षों में ऋण-व्यवस्थाओं ने गति पकड़ी है। विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशिआनिया और सीआईएस क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की गई हैं। ऋण-व्यवस्थाओं ने भारत के राजनीतिक, रणनीतिक और वाणिज्यिक हितों को बढ़ावा देने के साथ-साथ लाभार्थी देशों में भारत की राजनीतिक ख्याति को बढ़ाने का काम भी किया है। ऋण-व्यवस्थाएं भारत की बढ़ी आर्थिक मजबूती के साथ-साथ इन ऋण-व्यवस्थाओं के प्राप्तकर्ता देशों में बुनियादी ढांचागत विकास और क्षमता निर्माण में योगदान देने की प्रतिबद्धता को वैश्विक पटल पर लाने में भी मदद करती हैं। ऋण-व्यवस्थाएं प्राप्तकर्ता देशों के ऐसे बाजारों में जरूरी माल और सेवाओं के निर्यात में भी मददगार हैं, जहां भारत की मौजूदगी न के बराबर है। भारतीय निर्यातक इंडिया एक्ज़िम बैंक से अपने माल के लिए पात्र मूल्य हासिल कर सकते हैं और इसके लिए उन पर किसी तरह का रिकोर्स नहीं रहता। बैंक द्वारा शिपिंग दस्तावेजों के निगोशिएशन/ सेवाओं के प्रावधान के एवज में किया जाता है। भारतीय निर्यात कमाल के शिपमेंट पर इंडिया एक्ज़िम बैंक के जरिए पूरा भुगतान ले सकते हैं और इसमें उन्हें क्रेता या क्रेता देश से जुड़े किसी तरह के जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता।

ऋण-व्यवस्थाएं संप्रभु सरकारों को या उनकी नामित एजेंसियों को प्रदान की जाती हैं, ताकि उन देशों में क्रेता भारत से माल और सेवाओं का आस्थगित भुगतान शर्तों पर आयात कर सकें। बैंक द्वारा यथा 21 सितंबर, 2021 तक अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशिआनिया और सीआईएस क्षेत्रों के 62 देशों को 27.02 बिलियन यूएस डॉलर की ऋण प्रतिबद्धता के साथ 276 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं,जो भारत से निर्यातों के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध हैं। इस प्रकार ऋण-व्यवस्थाएं विकासशील देशों में भारत से परियोजनाओं, माल और सेवाओं के निर्यात के संवर्धन और सुगमीकरण के लिए प्रभावी साधन हैं।

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने जुलाई-सितंबर 2021के दौरान भारत सरकार की ओर से निम्नलिखित एक ऋण-व्यवस्था करार पर हस्ताक्षर किए :

1. मालदीव सरकार को `खेलों के लिए बुनियादी ढांचागत विकास' के वित्तपोषण के लिए 40 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई। इस ऋण-व्यवस्था करार पर हस्ताक्षर के साथ, इंडिया एक्ज़िम बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से मालदीव सरकार को अब तक कुल 1,130 मिलियन यूएस डॉलर की पांच ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। मालदीव सरकार को प्रदत्त इन ऋण-व्यवस्थाओं में मालदीव में 485 आवासीय इकाइयों का निर्माण, परियोजनाओं का विकास, ग्रेटर माले संपर्क परियोजनाएं, खेल और बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं का विकास और रक्षा परियोजनाओं तथा क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों के अंतर्गत वर्तमान परियोजनाएं शामिल हैं।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें :

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:
श्री सरोज खुंटिया, महाप्रबंधक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक,
ऑफिस ब्लॉक, टावर-1, 7वीं मंज़िल, एड्जेसेंट रिंग रोड,
किदवई नगर (पूर्व), नई दिल्ली 110023,
फोन : +91-11-24607700
ई-मेल: eximloc@eximbankindia.in

दास्तान-ए-कामयाबी

केन्या सरकार को ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत ब्लो मोल्डिंग मशीन, स्पेयर पार्ट और एसेसरीज़

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने केन्या सरकार को भारत सरकार के सहयोग से 15 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की है। यह ऋण-व्यवस्था केन्या में लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए प्रदान की गई है। इस संबंध में ऋण-व्यवस्था करार पर 11 जुलाई, 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे।

परियोजना का विवरण : इस संबंध में करार पर मैसर्स जगमोहन प्ला मैच प्रा. लि. और रेक्स प्लास्टिक्सलि. केन्या के बीच हस्ताक्षर किए गए और 20 अप्रैल, 2020 को इसे ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया गया।

परियोजना के स्कोप में 5 लीटर डबल स्टेशन ऑटोमैटिक ब्लो मोल्डिंग मशीन, इसके स्पेयर पार्ट्स और एसेसरीज की आपूर्ति, उनका इंस्टॉलेशन और कमिशनिंग के साथ-साथ व्यू स्ट्रिप अरेंजमेंट, ब्लो मोल्ड (5 लीटर), लीटर, अल्ट्रा 200 पॉइंट पैरिसन कंट्रोलर के लिए 4,6 कैविटी कैप मोल्ड, चिलर 30 लीटर, स्क्रैप ग्राइंडर - 12"/ 7.5 एचपी, 1000 लीटर एयर रिसीवर टैंक के साथ एयर कंप्रेशर-25 एचपी तथा स्पेयर्स (सीएफआर मोम्बासा पोर्ट) शामिल हैं।

परियोजना की कुल लागत - 121,300 यूएस डॉलर

परियोजना 29 अप्रैल, 2021 को सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई। ■

तिमाही गतिविधियां

भारतीय निर्यात-आयात बैंक की प्रबंध निदेशक नियुक्त की गईं सुश्री हर्षा बंगारी

सुश्री हर्षा बंगारी ने भारतीय निर्यात-आयात बैंक (इंडिया एक्ज़िम बैंक) की प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले वह बैंक की उप प्रबंध निदेशक पद पर कार्यरत थीं। सुश्री बंगारी ने 1995 में इंडिया एक्ज़िम बैंक जॉइन किया था। सुश्री बंगारी अनुभवी फायनेंस प्रोफेशनल हैं और उन्हें वित्तीय क्षेत्र में 26 वर्ष से अधिक का अनुभव है। उन्हें बैंक की सभी प्रक्रियाओं और व्यवसाय नीतियों की विशद जानकारी है। उन्हें ट्रेजरी और विदेशी मुद्रा संसाधनों से लेकर जोखिम प्रबंधन, ग्राहक सेवा, देयता प्रबंधन जैसे बैंक के समस्त क्रियाकलापों का अनुभव है।

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने की ब्रिक्स वार्षिक वित्तीय फोरम 2021 की मेजबानी

भारत की अध्यक्षता में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की थीम है, "ब्रिक्स15: निरंतरता, समग्रता और सहमति के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग।" ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग व्यवस्था के अंतर्गत सदस्य विकास बैंक के रूप में भारतीय निर्यात-आयात बैंक (इंडिया एक्ज़िम बैंक) द्वारा 08 सितंबर, 2021 को एक वर्चुअल प्लैटफॉर्म पर ब्रिक्स वित्तीय फोरम की मेजबानी की गई। भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई थीम के अनुरूप, ब्रिक्स वार्षिक वित्तीय फोरम की थीम "ब्रिक्स वित्तीय सहयोग के जरिए आर्थिक वृद्धि और समृद्धि बढ़ाना" रखी गई।

इस अवसर पर माननीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड ने अपने उद्घाटन संबोधन के दौरान कहा कि ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग व्यवस्था के अंतर्गत पांचों देशों का अनुभव मिलाकर 200 वर्षों का होता है। उन्होंने कहा कि बरसों के इस अनुभव का उपयोग जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए समाधान तलाशने और व्यापार तथा निवेशों को इस प्रकार सुगम बनाने के लिए किया जाना चाहिए कि सभी देशों के हित में सौहार्द और पारस्परिक वृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। इस फोरम में इंडिया एक्ज़िम बैंक के अतिरिक्त ब्रिक्स देशों के सदस्य विकास बैंकों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। अर्थात फोरम में ब्राज़ीलियन डेवलपमेंट बैंक (बीएनडीईएस), ब्राज़ील; स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (वीईबी.आरएफ), रूस; चाइना डेवलपमेंट बैंक (सीडीबी), चीन; डेवलपमेंट बैंक ऑफ सदर्न अफ्रीका (डीबीएसए), दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख शामिल हुए।

भारत के भावी निर्यात चैंपियनों को सहायता देने के लिए माननीय वित्त मंत्री ने किया उभरते सितारे फंड का शुभारंभ

भारत की माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने शनिवार, 21 अगस्त, 2021 को लखनऊ में 'उभरते सितारे फंड' (यूएसएफ) का शुभारंभ किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात संवर्धन मंत्री श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अपर सचिव श्री पंकज जैन विशेष रूप से उपस्थित रहे।

उभरते सितारे कार्यक्रम का संचालन इंडिया एक्ज़िम बैंक द्वारा सिडबी के साथ मिलकर किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मकसद छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय फलक पर ले जाना और उनके निर्यातों के सपनों को साकार करने में सामने आने वाली बाधाओं को दूर करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन कंपनियों को चिह्नित किया जाता है, जो आने वाले कल की निर्यात चैंपियन हो सकती हैं और जिनमें वैश्विक मांगों को पूरा करने की प्रबल संभावनाएं हैं। फिर उन कंपनियों को सहायता प्रदान की जाती है, जो तकनीकी, उत्पाद या प्रोसेस की दृष्टि से बेहतर स्थिति में हैं। यह कार्यक्रम उन चिह्नित उद्यमों की बाधाओं का पता लगाता है और उनकी वृद्धि तथा निर्यात रणनीति में उन्हें सहायता प्रदान करता है। यह सहायता वित्तीय और सलाहकारी सेवाओं, दोनों रूपों में दी जाती है। इसमें इक्विटी, ऋण और तकनीकी सहायता शामिल है।

कोविड के बाद के दौर में अफ्रीका के विकास के लिए अफ्रीका वित्त निगम को इंडिया एक्ज़िम बैंक ने प्रदान किया 100 मिलियन यूएस डॉलर का ऋण

अफ्रीका के अग्रणी अवसंरचना सेवा प्रदाता अफ्रीका वित्त निगम (एएफसी) को भारतीय निर्यात-आयात बैंक (इंडिया एक्ज़िम बैंक) द्वारा 100 मिलियन यूएस डॉलर का ऋण प्रदान किया गया। यह ऋण कोविड-19 महामारी के चलते अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं के पुनरुत्थान के लिए अत्यावश्यक बुनियादी ढांचागत जरूरतों को पूरा करने के लिए दिया गया है। इस 10 वर्षीय ऋण से मिलने वाली राशि के जरिए बुनियादी ढांचागत खामियों को पूरा करने के अफ्रीका के मिशन को जारी रखने में मदद मिलेगी। साथ ही यह ऋण इस महाद्वीप के लिए तत्काल आवश्यक संपोषी विकास को जारी रखने में मददगार होगा।

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत सेनेगल को प्रदान की 35.26 मिलियन यूएस डॉलर की क्रेता ऋण सुविधा

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने सेनेगल के अर्थव्यवस्था, योजना और सहयोग मंत्रालय के साथ 35.26 मिलियन यूएस डॉलर के एक क्रेता ऋण करार पर हस्ताक्षर किए। सेनेगल सरकार को यह क्रेता ऋण सुविधा, सेनेगल के टनफ से ज़िगिनकॉर तक (लगभग 92 किलोमीटर) 225 केवी की ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण और इंस्टॉलेशन के लिए प्रदान की गई है। यह निधियन राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) के क्रेता ऋण कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। इस परियोजना से सेनेगल के दक्षिणी क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इससे मुख्यतः तांबाकौंदा, ज़िगिनकॉर और टनफ क्षेत्रों को बिजली आपूर्ति की जा सकेगी और प्रति केडब्ल्यूएच लागत तथा परिचालन खर्च को कम करने में मदद मिलेगी। इससे ओएमवीजी (गाम्बिया रिवर बेसिन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन) विद्युत परियोजनाओं के साथ 225 केवी की विद्युत ट्रांसमिशन लाइन को इंटर-कनेक्ट किया जाएगा। इस परियोजना का निष्पादन कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। ■

विभिन्न देशों का आर्थिक परिदृश्य

किर्गिज़ गणराज्य

किर्गिज़ गणराज्य का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2021 में 2.5% बढ़ने का अनुमान है। इस देश की अर्थव्यवस्था व्यापार, पूंजी प्रवाह और निवेश के लिए चीन और रूस पर ही निर्भर है। इससे यहां आर्थिक झटकों और अस्थिरता की आशंका भी रहती है। इसके अलावा, यह देश मुख्य रूप से तेल आयात और कमोडिटी निर्यात पर भी निर्भर है। इससे यहां की अर्थव्यवस्था पर वैश्विक ऊर्जा और कमोडिटी की कीमतों में प्रतिकूल प्रवृत्तियों के असर का खतरा बना रहता है। यही कारण है कि 2021 में वैश्विक तेल और खाद्य कीमतों में उछाल आने से इस देश में मुद्रास्फीति का औसत बढ़कर 10.2% तक पहुंचने का अनुमान है। रूस की मुद्रा `रूबल' में उतार-चढ़ाव भी किर्गिज़ मुद्रा `सोम' के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। इस उतार-चढ़ाव के चलते 2021 में सोम का मूल्य एक यूएस डॉलर के मुकाबले 85.14 तक पहुंचने के आसार हैं। यहां 2020 में चालू खाते में अधिशेष की स्थिति थी। लेकिन 2021 में फिर सकल घरेलू उत्पाद के करीब 9% तक घाटे की आशंका है, अनुमान है। इसका मुख्य कारण बाहरी मांग की तुलना में घरेलू मांग में तेजी से आयात अधिक होने की संभावना है। वैश्विक स्तर पर तेल की ऊंची कीमतों से भी व्यापार घाटा बढ़ने की आशंका है। हालांकि 2021-22 में रेमिटैंस और सोने के निर्यात के साथ-साथ बिजली के निर्यात से बाहरी स्थितियों से कुछ हद तक निपटने में सहयोग मिल सकता है।

श्रीलंका

श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था 2021 में 3% का मामूली सुधार आ सकता है। इसमें 2020 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 3.6% की गिरावट दर्ज की गई थी। इस गिरावट का प्रमुख कारण कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर रोकने के लिए पूरे देश में लगाए गए सख्त प्रतिबंध थे, जिनसे आर्थिक गतिविधियों में भी बाधाएं आईं। लेकिन अब जैसे-जैसे स्थिति सामान्य हो रही है, अर्थव्यवस्था को मर्चेंडाइज निर्यातों से प्राप्य राशियों में वृद्धि से मजबूती मिलने की उम्मीद है। लेकिन मुद्रा की कीमत लगातार गिर रही है, वहीं खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं। इससे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2020 के 4.6% की तुलना में 2021 में 5.1% तक पहुंचने का अनुमान है। चालू खाते में भी घाटा बढ़ने का अनुमान है। यह 2021 में जीडीपी का 2.9% रह सकता है। जबकि 2020 में यह जीडीपी का 1.3% था। चालू खाता घाटा बढ़ने का मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ना और आधारभूत ढांचा निर्माण के लिए आयात की बढ़ी हुई मांग है। पर्यटन से होने वाली आय की स्थिति भी अभी सामान्य नहीं हुई है, बल्कि कम ही रही है। इससे सेवा क्षेत्र पर भी मंदी का असर रहने का अनुमान है। उत्पाद और व्यापार खाते में लगातार घाटे की स्थिति है। इससे श्रीलंकाई रुपये का और अवमूल्यन होने की आशंका है। वर्ष 2020 में 1 यूएस डॉलर के मुकाबले इसकी कीमत 185.6 श्रीलंकाई रुपये थी। जबकि 2021 में 1 यूएस डॉलर के मुकाबले यह कीमत 197.4 श्रीलंकाई रुपये रह सकती है।

नीदरलैंड

उम्मीद की जा रही है कि 2021 में यहां की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के प्रभाव से उबर जाएगी। पिछले संकुचन के बाद वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 3.4% तक बढ़ने की उम्मीद है। वर्ष 2020 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 3.8% की कमी दर्ज की गई थी। इसका मतलब यह भी हुआ कि नीदरलैंड ने यूरोपीय संघ की अधिकांश अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम गंभीर मंदी का सामना किया है। क्योंकि 2020 के दौरान ईयू के सकल घरेलू उत्पाद में औसतन 6.6% की गिरावट दर्ज की गई है। जाहिर है, इस डच अर्थव्यवस्था की संरचना, उल्लेखनीय नीतिगत सहयोग और कोरोना संक्रमण के दौरान तालाबंदी आदि की रणनीति भिन्न रही है। उच्च डिजिटलीकरण, अच्छा विविधतापूर्ण निर्यात और आतिथ्य तथा पर्यटन जैसी उच्च संपर्क सेवाओं पर अपेक्षाकृत कम निर्भरता इस अर्थव्यवस्था की विविष्टताएं हैं। वर्ष 2020 में यहां उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बीते चार साल के निचले स्तर 1.1% पर रहा। लेकिन 2021 में यह सूचकांक 2.1% तक पहुंच गया है। इसका कारण स्पष्ट है कि यहां उपभोक्ता खर्च बढ़ा है। जबकि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति में अब तक कमी बनी हुई है। अमेरिका के संघीय रिज़र्व बैंक (फेड रिज़र्व) की मौद्रिक नीति 2020 में ढीली ही रही है। नतीजतन, यूएस डॉलर की तुलना में यूरो की स्थिति 2021 में भी बेहतर रहने की संभावना है। वर्ष 2020 में 1 यूरो जहां 1.14 यूएस डॉलर के बराबर था, वहीं 2021 में 1 यूरो की कीमत 1.20 यूएस डॉलर तक रह सकती है। विश्व स्तर पर वाणिज्यिक वस्तुओं के व्यापार में तेजी और मजबूत प्राथमिक आय प्रवाह से यहां 2021 में भी चालू खाता अधिशेष की स्थिति में रह सकता है। वर्ष 2020 में चालू खाते का अधिशेष जीडीपी का 7% था। वहीं 2021 में यह 9.5% तक पहुंच सकता है।

यूक्रेन

यूक्रेन का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2021 में 4% की दर से बढ़ने का अनुमान है। जबकि 2020 में इसमें 4% की गिरावट दर्ज की गई थी। बढ़त का अनुमान मुख्य रूप से उपभोक्ता खर्च में वृद्धि की संभावना पर आधारित है। कोरोना संक्रमण से जुड़े प्रतिबंधों में भी अब ढील दी जा रही है। इससे बढ़त की संभावना को मजबूती मिली है। हालांकि निवेश के कोरोना-पूर्व की स्थिति में पहुंचने के लिए अल्प अवधि में कुछ संघर्ष करना पड़ सकता है। यहां घरेलू स्तर पर खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हुई है। जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में बढ़त का रुख रहा है। इससे 2021 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 8.8% के स्तर पर उछल सकता है। जबकि 2020 में यह 2.7% के स्तर पर था। हालांकि वेतन भत्तों में भी वृद्धि का अनुमान है। इससे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बढ़त में कुछ संतुलन आ सकता है। यूक्रेन की मुद्रा रिव्निया (यूएएच) का भी 2020 की तुलना में थोड़ा अवमूल्यन हो सकता है। वर्ष 2020 में 1 यूएस डॉलर के मुकाबले इसका मूल्य 27 यूएएच था। जबकि 2021 में 1 यूएस डॉलर के मुकाबले इसकी कीमत 27.9 यूएएच के बराबर हो सकती है। नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन (एनबीयू) ब्याज दरों में वृद्धि की तरफ काफी सतर्क है। वहीं, बाहरी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी आ रही है। इसी का असर रिव्निया के अवमूल्यन के रूप में दिख रहा है। यूक्रेन के चालू खाते में 2020 में 3.3% के अधिशेष की स्थिति थी। लेकिन 2021 में इसमें 0.1% के घाटे की स्थिति रह सकती है। चालू खाते का यह घाटा बढ़ भी सकता है, क्योंकि 2020 में फसल काफी खराब रही है। साथ ही वाणिज्यिक वस्तुओं और धातुओं की कीमतों में भी उछाल देखा गया है। ■

मुद्रा की प्रवृत्तियां

यूएस डॉलर

$ कोरोना संक्रमण के वैश्विक प्रसार के प्रभाव में दुनियाभर के बाजारों में अस्थिरता की स्थिति रही है। इसके बावजूद यूएस डॉलर ने पूरे साल मजबूती बनाए रखी। उम्मीद की जा रही है कि आगे भी इसकी स्थिति सुरक्षित मुद्रा के रूप में बनी रहेगी।

अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) इस वर्ष तीन गुना तक ऊपर पहुंचा है। अगस्त 2021 में यह 4% पर रहा। अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले यह तुलनात्मक रूप से बहुत ऊंचाई पर था। मुद्रास्फीति के साथ-साथ अमेरिकी अर्थव्यवस्था रोजगार के अवसर बढ़ाने के मोर्चे पर भी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही है। इसका मुख्य कारण कोरोना के डेल्टा वैरिएंट के मामले बढ़ने को माना जा रहा है। इससे अर्थव्यवस्था में सुधार की तरफ हो रही वृद्धि प्रभावित हो सकती है। अमेरिका में छह प्रतिस्पर्धी मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी मुद्रा डॉलर का सूचकांक तैयार किया जाता है। यह मध्य अगस्त की तुलना में निचले स्तर पर जाता दिख रहा है। तब यह 93.729 अंकों के साथ शीर्ष पर था। जबकि सितंबर के पहले सप्ताह में यह 91.947 अंक पर रहा। तब अमेरिकी वेतन भुगतान रिपोर्ट में आशंका जताई गई थी कि संघीय रिज़र्व बैंक (फेड रिज़र्व) सितंबर में होने वाली नीतिगत बैठक के दौरान सरकारी प्रोत्साहन योजना पर अंकुश लगा सकता है।

भारतीय रुपये के संदर्भ में 15 सितंबर, 2021 को 1 यूएस डॉलर की कीमत 73.63 रुपये रही।

फिलीपींस पेसो

₱ फिलीपींस की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के कारण आई मंदी की स्थिति से बाहर निकल चुकी है। वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के हिसाब से इसने बीते तीन दशक की तुलना में सबसे तेज गति से सुधार किया है। फिर भी कोविड-19 से संबंधित सख्त प्रतिबंध सुधार की रफ्तार को प्रभावित कर सकते हैं। अनुमान है कि फिलीपींस की मौद्रिक नीति 2021 की शेष अवधि में भी समझौतापरक बनी रह सकती है। जून 2021 को समाप्त तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 11.8% की दर से वृद्धि हुई है। इसका कारण एक साल पहले कोविड-प्रभावित स्थिति की तुलना में घरेलू मांग में आई तेजी को माना जा रहा है।

फिर भी कोविड-19 के डेल्टा वैरिएंट से जुड़ी चिंताएं कायम रहीं। इससे यूएस डॉलर के मुकाबले पेसो (पीएचपी) की स्थिति जून से मध्य अगस्त के बीच ही 7% तक कमजोर हुई। इससे यह मुद्रा एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन वाली मानी गई। बीते कुछ महीनों में थाईलैंड की मुद्रा थाई `बात' का प्रदर्शन भी इसी तरह खराब रहा है। बीते तीन साल में अपनी सबसे बड़ी मासिक गिरावट की स्थिति पर पहुंचने के बाद अभी इस मुद्रा के और अवमूल्यन की आशंका है। इसके पीछे दो कारण माने जा रहे हैं। पहला- वायरस का संक्रमण अभी देश को फिर परेशान कर सकता है। दूसरा- मुद्राओं के वैश्विक वरीयता क्रम में पेसो के अभी और नीचे जाने का जोखिम बना हुआ है। जुलाई से सितंबर की तिमाही में कारोबार के लिए 1 यूएस डॉलर की तुलना में 47.54 से 51.09 के बीच पेसो का इस्तेमाल हुआ था।

15 सितंबर, 2021 को 1 यूएस डॉलर की तुलना में पीएचपी का मूल्य 49.68 पीएचपी रहा।

सिएरा लियोन- लियोन

Le सिएरा लियोन की अर्थव्यवस्था भी कोविड-19 की वजह से उपजी मंदी के प्रभाव से धीरे-धीरे उबर रही है। वर्ष 2020 के अनुमान के मुकाबले 2021 में इसने 0.8% बिंदु के सुधार के साथ वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 2021 में 3% की वृद्धि दर्ज की है। यह वृद्धि विशेष तौर पर कृषि, खनन और सेवा क्षेत्र में हुए सुधार को प्रतिबिंबित करती है। कोविड से जुड़ी बंदिशों में ढील और सरकार के त्वरित कार्रवाई आर्थिक प्रतिक्रिया कार्यक्रम (क्यूईआरपी) के कारण यह संभव हो सका।

वर्ष 2020 में बजट घाटा करीब दोगुना हो गया था। इसके दो प्रमुख कारण थे। एक तो सरकार के पास राजस्व की कमी थी। दूसरा, कोरोना से इंतजामों पर सरकार को काफी रकम खर्च करनी पड़ी। बजट घाटा 2023 तक जीडीपी के 2.4% के स्तर तक पहुंचने का अनुमान है। इसके भी प्रमुख रूप से दो ही कारण हैं। पहला- कोरोना से जुड़े इंतजामों पर खर्च लगातार कम हो रहे हैं। दूसरा- अर्थव्यवस्था में भी धीरे-धीरे सुधार होने से राजस्व का प्रवाह भी बढ़ने की उम्मीद है। बैंक ऑफ सिएरा लियोन ने 13 अगस्त, 2021 को अपनी मुद्रा लियोन (एसएलएल) के पुनः वर्ग-निर्धारण की घोषणा की है। इसके बाद हजार के नोटों को वैध चलन से बाहर कर दिया गया है।

15 सितंबर, 2021 को 1 यूएस डॉलर की तुलना में इसका मूल्य 10,336 एसएलएल रहा।

ब्राज़ीलियाई रियाल

R$ ब्राज़ील की मुद्रा रियाल (बीआरएल) का मूल्य पिछले तीन महीने 1 डॉलर के मुकाबले 4.89 से 5.48 के बीच झूल रहा है। निर्यातों में आए उछाल से ब्राज़ील को काफी फायदा हुआ है। कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद चीन से बढ़ी मांग ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। कमजोर विनिमय दर भी इसकी पृष्ठभूमि में रही।

रियाल का मूल्य 10 अगस्त 2021 को पिछले तीन महीनों के दौरान सबसे ऊपर 5.48 तक पहुंचा था। उस समय कोरोना के डेल्टा वैरिएंट के मामले सभी देशों में तेजी से सामने आ रहे थे। इससे वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियां फिर धीमी होने की आशंका थी। यह भी आशंका थी कि अमेरिका केंद्रीय बैंक फेड रिजर्व जल्द ही असाधारण प्रोत्साहन योजना को रोक सकता है। ब्राजील में उपभोक्ता मूल्य यानी महंगाई भी बीते महीने के मुकाबले मध्य अगस्त में अपेक्षा से अधिक करीब 0.89% की दर से बढ़ी है। इसी तरह वार्षिक मुद्रास्फीति की दर भी मध्य अगस्त में 9.3% रही। इसके पीछे मुख्य भूमिका वहां के केंद्रीय बैंक की देखी गई, जिसने लगातार पांचवीं बार ब्याज दरों में बढ़ोत्तरी की है। इससे रियाल का मूल्य तथा महंगाई की दर अभी और ऊपर जाने की आशंका है।

15 सितंबर, 2021 को 1 यूएस डॉलर की तुलना में इसका मूल्य 5.27 बीआरएल रहा।

एक्ज़िम मित्र

भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने और व्यापार वित्त, ऋण बीमा सुविधाओं तथा भारतीय उद्यमियों के बीच व्यापार संबंधी अन्य जानकारियों की उपलब्धता में विषमता को कम करने के लिए एक्ज़िम बैंक ने 'एक्ज़िम मित्र' नाम के एक पोर्टल की शुरुआत की। एक्ज़िम मित्र निर्यातों के लिए ऋण की उपलब्धता और व्यापार संबंधी जानकारी देने के दोहरे उद्देश्य के साथ काम करता है। एक्ज़िम मित्र भारतीय उद्यमियों से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संबंध में मिलने वाले सवालों को हल करने में मदद करता है, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:

मर्चेंट निर्यातक और विनिर्माता निर्यातक के बीच अंतर

मर्चेंट निर्यातक का अर्थ होता है, ऐसा व्यक्ति जो व्यापारिक गतिविधि में शामिल है और वस्तुओं का निर्यात करता है या निर्यात करने की संभावनाओं पर काम कर रहा है। मर्चेंट निर्यातक किसी विनिर्माता से सामग्री खरीदता है और अपनी फर्म के नाम पर निर्यात करता है। यहां मर्चेंट निर्यातक अंतरराष्ट्रीय बाजार से ऑर्डर हासिल करता है। मर्चेंट निर्यातक के पास अपनी विनिर्माण इकाई या प्रसंस्करण फैक्टरी नहीं होती है। मर्चेंट निर्यातक उत्पादन योग्य वस्तुओं को निर्यात कंसाइनमेंट की सील लगाकर या बिना सील के ही सीधे विनिर्माता के परिसर से या छूट अथवा बॉन्ड के अंतर्गत दावे के तहत अपने परिसर से निर्यात कर सकता है।

विनिर्माता निर्यातक का अर्थ होता है, ऐसा व्यक्ति जो माल का विनिर्माण करता है और उस माल का निर्यात करता है या निर्यात करने की संभावनाओं पर काम कर रहा है। विनिर्माता निर्यातक अपने कारखाने में कच्चे माल को खरीदता और उसे संसाधित करता है तथा तैयार उत्पादों का निर्यात करता है। यहां विनिर्माता निर्यातक अपने नाम से निर्यात आदेश हासिल कर निर्यात करता है।

भारत से समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए एमपीईडीए में पंजीकरण की जानकारी

किसी निर्यातक (मर्चेंट और विनिर्माता निर्यातक दोनों) के रूप में पंजीकरण को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) अधिनियम, 1972 की धारा 9(2)(एच) के तहत किया जाता है और इसे एमपीईडीए नियमों के नियम 40-42 के साथ पढ़ा जाता है।

नियम 40 (1) "कोई भी व्यक्ति इस नियम के लागू होने की तारीख से दो महीने की अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी समुद्री उत्पाद का निर्यात नहीं करेगा, जब तक कि उसे प्राधिकरण के साथ निर्यातक के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया हो। पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होने के एक महीने की अवधि के दौरान आवेदक को निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी। यह नियम निम्नलिखित द्वारा समुद्री उत्पादों के निर्यात पर लागू नहीं होगा:

- केंद्र सरकार या समुद्री निर्यात प्राधिकरण या समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए केंद्र सरकार अथवा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा या उनकी ओर से;
- उपहार पार्सल या नमूने भेजने के माध्यम से (अधिकतम ₹ 10,000/-);
- यात्रियों के व्यक्तिगत प्रभाव के रूप में (अधिकतम ₹ 5000/-);
- किन्हीं गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए (अधिकतम ₹ 25,000/-); और
- विदेश में किसी भी प्रदर्शनी के लिए (अधिकतम ₹ 1,00,000/-)

सौंदर्य प्रसाधनों के लिए विनिर्माण लाइसेंस और आयात मानकों संबंधी जानकारी

सौंदर्य प्रसाधनों के लिए विनिर्माण लाइसेंस राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं। सौंदर्य प्रसाधन तब तक आयात नहीं किए जा सकते, जब तक कि ये अनुसूची एस और अनुसूची क्यू या उन पर लागू गुणवत्ता और सुरक्षा के किन्हीं अन्य मानकों तथा औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियम, 1945 के अंतर्गत अन्य प्रावधानों पर खरे नहीं उतरते। यदि किसी सौंदर्य प्रसाधन को अनुसूची एस में शामिल नहीं किया गया है, तो उसका मूल विनिर्माता देश में लागू नियमों और मानकों पर खरा उतरना जरूरी है।

संयंत्र और संयंत्र उत्पादों के लिए निर्यात प्रमाणन संबंधी जानकारी

संयंत्रों और संयंत्र उत्पादों का निर्यात निरीक्षण और फायटोसैनिटरी प्रमाणन अंतरराष्ट्रीय संयंत्र संरक्षण सम्मेलन (आईपीपीसी) के अनुच्छेद-4 के अनुसार किया जाता है और देखा जाता है कि ये सदस्य देशों के विधिक मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं। फायटोसैनिटरी प्रमाण पत्र आयातक देश के वर्तमान पीक्यू नियमों के साथ-साथ आईपीपीसी के अनुच्छेद-5 के तहत निर्धारित मॉडल प्रारूपों में जारी किए जाते हैं। इस तरह के प्रमाण पत्र निर्यातक देश में तकनीकी रूप से योग्य और विधिवत प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा संयंत्रों और संयंत्र उत्पादों के सावधानीपूर्वक निरीक्षण के बाद जारी किए जाते हैं तथा इसमें आयातक देश द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त घोषणाएं एवं यदि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कोई विशेष विवरण दिया जाता है तो उसे भी शामिल किया जाता है।

तदनुसार, निर्यात निरीक्षण और फायटोसैनिटरी प्रमाणन के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा प्राधिकारियों को अधिसूचित किया जाता है। फायटोसैनिटरी प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा प्रतिबंधित/प्रतिबंधित संयंत्र उत्पादों की विस्तृत सूची के लिए निर्यात-आयात नीति के साथ-साथ सीआईटीईएस के प्रावधानों को संदर्भित किया जा सकता है।

व्यापार वार्ताओं (साख पत्र (एलसी) /करार आदि) करते समय, निर्यातक को आयातक देश से निर्यात की जा रही वस्तु के संबंध में वर्तमान संयंत्र संगरोध विनियमों के बारे में आयातक के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट या आयातक देश द्वारा जारी परमिट की एक प्रति जहां भी लागू हो, में लगाना सुनिश्चित करना चाहिए। फायटोसैनिटरी प्रमाण पत्र आयातित देश की अपेक्षाओं के अनुसार जारी किया जाता है। ये अपेक्षाएं कॉन्ट्रैक्ट या आयातक देश द्वारा जारी परमिट में विधिवत परिलक्षित होते हैं। ■

आंकड़ों में भारतीय अर्थव्यवस्था

मर्चेंडाइज व्यापार

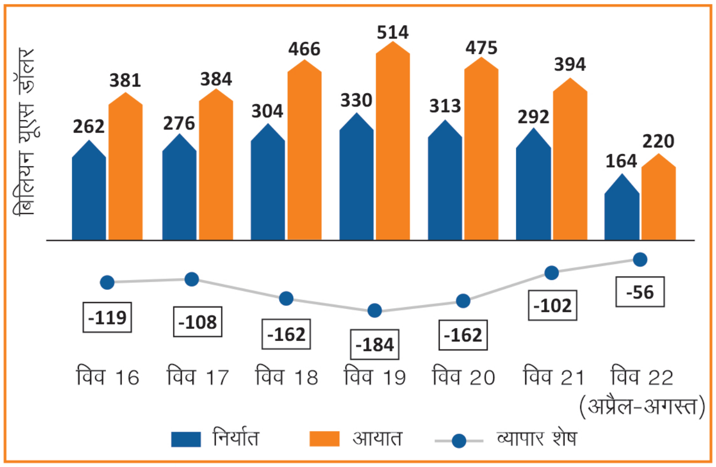

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

सेवा क्षेत्र में व्यापार

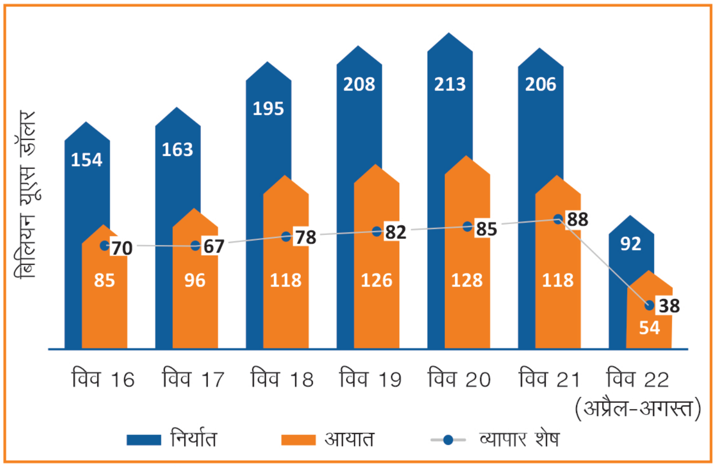

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह

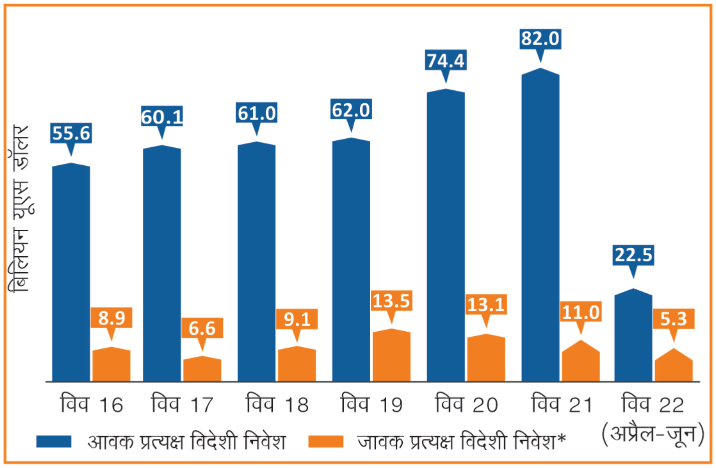

नोट: - जावक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तहत इक्विटी, लोन और गारंटियों के रूप में दी गई विदेशी सहायता शामिल है।*

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति

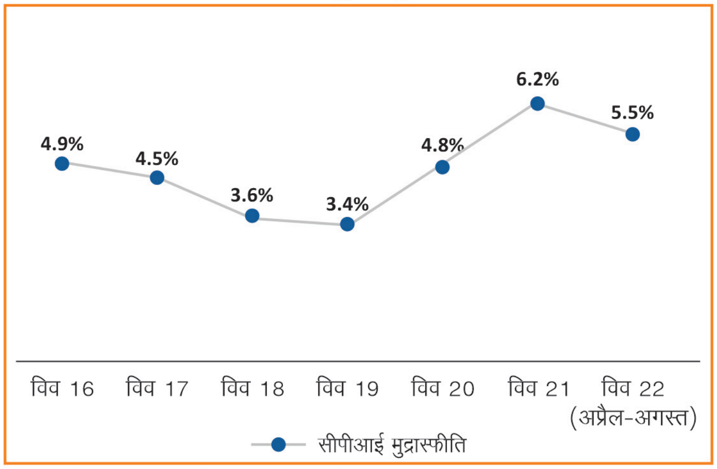

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

चालू खाता घाटा (सीएडी)

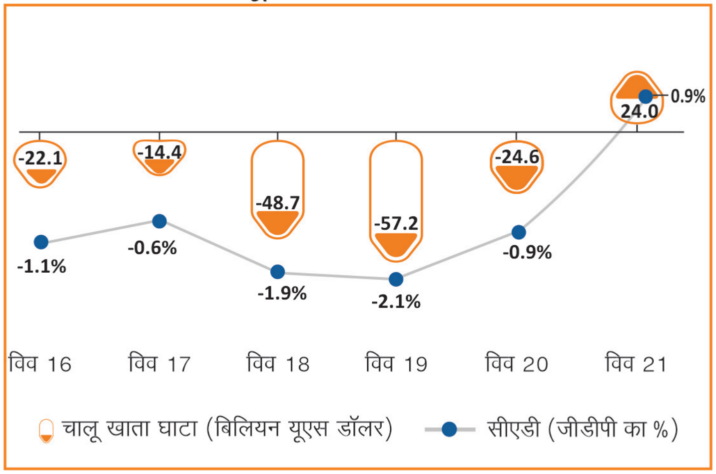

स्रोत: आरबीआई

क्षेत्रवार उत्पादन

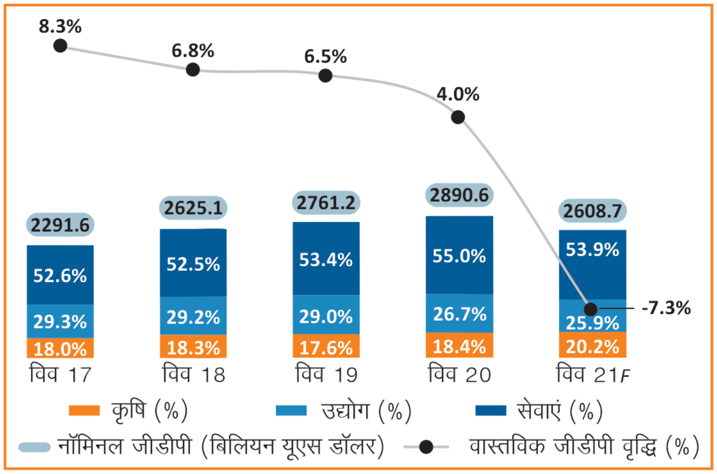

नोट: F अग्रिम पूर्वानुमान

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान (आईआईएफ) तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार